मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्षः 9 अंक 39
शुक्रवार, 14 अगस्त 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

बीजेपी थोप रही अपना सिस्टम, कांग्रेस देगी India को बोलने का मौकाः राहुल गांधी

नई दिल्ली, 13 अगस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को NEET-UG पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। नई दिल्ली में 'रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन' में बोलते हुए, गांधी ने आरोप लगाया कि BJP की राजनीतिक विचारधारा भारत पर ऐसी व्यवस्था थोपना है जिससे उन्हें और कुछ खास लोगों को फायदा हो। उन्होंने कहा, हमारा काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना है। सम्मेलन में बातचीत के अंदाज में अपनी बात रखते हुए गांधी ने जोर दिया कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी द्वारा थोपी गई व्यवस्था को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जो हो रहा था, वह यह है कि छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं। वे परेशान हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहती है—नहीं। हम जंतर-मंतर पर व्यवस्था कायम करेंगे। आप अपनी बात नहीं रख सकते। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने विरोध-प्रदर्शन के हालात की तुलना एक रेप पीड़िता के परिवार के साथ हुई अपनी बातचीत से की।

उन्होंने याद करते हुए कहा कि आज एक महिला मेरे पास आई, जिसकी बेटी के साथ चार साल पहले उत्तराखंड में रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। वह रो रही थी, अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम कहता है—'माफ कीजिए, हम आपको अपनी बात कहने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप

अपनी बात कहेंगी तो अव्यवस्था फैल जाएगी'। उन्होंने आगे कहा कि तो उनका काम और उनकी राजनीतिक सोच भारत पर एक ऐसा सिस्टम थोपना है, जिससे उन्हें और कुछ खास लोगों को फायदा हो। और हमारा काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना और उस सिस्टम को तोड़ना है। CJP की अगुवाई में जंतर-मंतर पर हो रहा विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ। संसद में विपक्षी पार्टियों ने गृह मंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर बयान देने की मांग की है।

गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आज के भारत को न समझने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे हों और अचानक कहें कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप तो कुछ जोकरों से लड़ रहे हैं। आपको डर कैसे लग सकता है? आप असल में कुछ जोकरों, ऐसे मसखरों से लड़ रहे हैं जिन्हें हमारी फि लॉसफी या हमारे इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ऋर में मौजूद अपने दोस्तों के बारे में यह बात साफ तौर पर कह सकता हूँ। यह बात मेरे लिए बिल्कुल साफ है। उन्होंने आगे कहा कि असल में, ज्यादातर लोगों के लिए यह साफ है कि इन लोगों को भारत की कोई समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोई आज के भारत से नहीं जुड़ सकता, वह भारत को समझ नहीं सकता। भारत को समझने के लिए, आप 3,000 साल पुराने भारत को नहीं समझ सकते।

क्या आप नहीं चाहते कि लोग स्वस्थ रहें? फूड पैकेट पर सुप्रीम कोर्ट से FSSAI को फटकार

नई दिल्ली, 13 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) से कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी वाले लेबल लगाने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या रेगुलेटर नहीं चाहता कि लोग सेहतमंद रहें और क्या वह फूड इंडस्ट्री के दबाव में आ रहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चेतावनी वाले लेबल लगाने की मांग की गई थी, ताकि ग्राहक पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स से जुड़े न्यूट्रिशन संबंधी जोखिमों को आसानी से पहचान सकें। इसने इस प्रस्ताव को लेकर ऋरअककी साफ-साफ हिचकिचाहट पर आपत्ति जताई और सवाल किया कि लोगों में

जागरूकता बढ़ाने के मकसद वाले उपाय में देरी क्यों की जा रही है।

बेंच ने पूछा कि क्या आप कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं? साथ ही, यह आरोप भी लगाया कि फूड मैन्युफैक्चरर्स का दबाव रेगुलेटर के रवैये पर असर डाल रहा हो सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि मामला किसी खास फूड प्रोडक्ट या बनाने वाली कंपनी को निशाना बनाने का नहीं है, बल्कि यह पक्का करने का है कि ग्राहकों को कुछ भी खरीदने से पहले पूरी जानकारी मिले। बेंच ने पूछा, आपने अब तक क्या किया है? हमें पता है कि आप पर कितना दबाव है। क्या आप खुद ऐसा करेंगे या हमें कोई आदेश जारी करना होगा? केंद्र और ऋरअक को इस मामले पर अपना फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया गया है।

यह मामला ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले खाने-पीने की चीजों के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर लेबलिंग से जुड़ी एक PIL से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले FSSAI से इस मामले की जांच करने और सही उपाय करने पर विचार करने को कहा था। गुरुवार की सुनवाई के दौरान, केंद्र और FSSAI की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाहर ने दलील दी कि ऐसे वॉर्निंग लेबल लगाने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि कई पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से नमक या फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है।

'हर घर तिरंगा' से हर भारतीय जुड़ा, अमित शाह बोले- यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक

नई दिल्ली, 13 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत तिरंगा फहराया और कहा कि इससे हर भारतीय के दिल में देशभक्ति और गर्व की भावना मजबूत होती है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर कहा कि आज, नई दिल्ली में अपने आवास पर मैंने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया यह अभियान आज हर भारतीय के दिल में देशभक्ति और गर्व की भावना को और मजबूत कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी तिरंगे से जुड़ रहे हैं और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को सशक्त बना रहे हैं।

'हर घर तिरंगा' अभियान

'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत शुरू किया गया था, ताकि नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लाने और भारत की आजादी के जश्न के हिस्से के तौर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह अभियान इस सोच पर आधारित था कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोगों का रिश्ता पारंपरिक रूप से ज्यादा औपचारिक और संस्थागत रहा है, न कि राष्ट्रीय गौरव की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के रूप में।

नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज घर लाने के लिए प्रोत्साहित करके, इस पहल का मकसद तिरंगे को देश के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बनाना था, साथ ही यह राष्ट्र-निर्माण और राष्ट्रीय एकता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को भी दशार्ता है। इस साल, हर घर तिरंगा 2026 को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की भावना को समर्पित किया जा रहा है।

राहुल गांधी का अहंकार ले डूबा मॉनसून सत्रः रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली, 13 अगस्त। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र के बेकार जाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अहंकार, जिद और हक जताने की सोच को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार होने के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के अहंकार और पूरी तरह से अनुशासनहीनता की वजह से संसद का पूरा सत्र बर्बाद हो गया।

प्रसाद ने कहा कि संसद का पूरा मॉनसून सत्र एक नेता के अहंकार, अनुशासन की कमी और ज़िद की भेंट चढ़ गया। मैं यह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। संसद का पूरा मॉनसून सत्र विपक्ष के नेता के अहंकार, मनमानी, हक जताने की सोच और पूरी तरह से अनुशासनहीनता की भेंट चढ़ गया। प्रसाद ने बताया कि शाह ने पुलिस की कार्रवाई पर बहस में शामिल होने और विपक्ष की सभी दलीलों का जवाब देने की पेशकश की थी।

उन्होंने कहा कि कल आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री खुद मीडिया के सामने आए और कहा, 'मैं पूरी बहस सुनने और पुलिस से जुड़ी घटनाओं पर उनकी सभी दलीलों का जवाब देने के लिए 24 घंटे तक बैठने को तैयार हूँ। मैं हर एक बात का जवाब दूँगा।' हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और सदन में यह बात उठाई कि हम बहस के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि माननीय स्पीकर ने भी कहा कि बहस होनी चाहिए।

राहुल गांधी के शाह के इस्तीफे की मांग वाले बयानों की आलोचना करते हुए, प्रसाद ने पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में

उनकी समझ पर सवाल उठाए। प्रसाद ने कहा कि लेकिन फिर उनके राहुल गांधी के दो 'बेवकूफी भरे' बयान आए, जिन्हें मैं कोट करना चाहूंगाः 'अगर उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वह एक अक्षम और बेकार मंत्री हैं, इसलिए उन्हें फिर भी इस्तीफा देना चाहिए।' मिस्टर राहुल गांधी, क्या आपको गवर्नेंस की बुनियादी समझ भी नहीं है? क्या गृह मंत्री कभी फायरिंग का आदेश देते हैं? इसका क्या मतलब है? इसके लिए नियम हैं; एक प्रोटोकॉल है। वहां मौजूद मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी, या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस--उनसे सलाह लेने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। फिर भी, आपने यह मुद्दा उठाया।

प्रसाद ने संसदीय राजनीति के प्रति गांधी के नजरिए पर भी हमला करते हुए कहा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की मांगों के अनुसार नहीं चल सकती।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, देश की राजनीति आपकी ज़िद पर नहीं चलेगी। मिस्टर राहुल गांधी, देश और संसद की राजनीति और व्यवस्था आपके अहंकार, हक जताने की भावना और 'मैं जो चाहूंगा वही करूंगा; या तो मेरी बात मानो या रास्ता नापो' वाली सोच के दबाव में नहीं चलेगी। लोकतंत्र ऐसे काम नहीं करता। हम पिछले 10-12 दिनों में हुई घटनाओं के इस सिलसिले की कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी कोई सबक नहीं सीखते। बीजेपी नेता ने झारखंड में छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया और इस मामले पर कांग्रेस नेता की चुप्पी पर सवाल उठाए।

टीएमसी बागी लोकसभा सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी

कोलकता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपने बागी लोकसभा सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और पार्टी अगले 7-10 दिनों में उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिकाएं दायर कर सकती है। ळटउ जून से ही इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। जून में ही पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने बगावत कर दी थी और 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) के साथ जुड़ने की घोषणा करते हुए BJP के नेतृत्व वाले 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' (NDA) को समर्थन देने का वादा किया था। बागी गुट में शामिल प्रमुख सांसदों में काकोली घोष दस्तीदार, यूसुफ पठान, सायनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रसून बनर्जी, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीकुर रहमान, अबू

ताहिर खान, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, दीपक अधिकारी (देव), अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार, बापी हलदर, माला रॉय और मिताली बाग शामिल हैं।

यह राजनीतिक संकट जून में 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद शुरू हुआ। इसके बाद बागी गुट ने NCPI के साथ विलय का दावा किया।

श्रीलंका में ध्रुव जुरेल की अग्निपरीक्षा, स्पिन के खिलाफ सुधार पर नजर; राहुल से लिया गुरुमंत्र

डार्विन, 13 अगस्त। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल नेट्स में अपनी बल्लेबाजी को धार देने में जुटे हैं। गॉल की गर्म परिस्थितियों में जुरेल ने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के खिलाफ लंबे समय तक अभ्यास किया। वह फील्डिंग सेशन में भी काफी सक्रिय नजर आए और स्लिप कॉर्डन में कई शानदार कैच पकड़े। हालांकि, जुरेल के लिए यह टेस्ट सीरीज उनके करियर के लिहाज से बेहद अहम है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में पिछले साल अक्तूबर में शानदार शतक लगाने के बाद उनकी अगली सात टेस्ट पारियों में उनके स्कोर 44, 6, 14, 13, 0, 2 और 19 रहे हैं।

इस दौरान वह पांच बार स्पिन गेंदबाजों का शिकार बने हैं। गॉल की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और ऐसे में जुरेल के सामने चुनौती और बड़ी होगी। श्रीलंका के अनुभवी स्पिनर प्रभात जयसूर्या भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जुरेल के लिए एक और दबाव सरफराज खान की मौजूदगी है। सरफराज भी इसी बल्लेबाजी क्रम में दावेदारी पेश कर रहे हैं और स्पिन के खिलाफ उनके पास कई तरह के शॉट हैं। वह स्वीप, रिवर्स स्वीप और ट्रैक पर आगे बढ़कर खेलने के अलावा कट और लेट डैब जैसे शॉट भी खेलते हैं। इसके उलट जुरेल आमतौर पर स्पिनरों के खिलाफ गेंदबाज की गलती का इंतजार करते हैं और जोखिम कम लेने की कोशिश करते हैं।

TIWARI'S
SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
✓ 34+ Years of Academic Excellence
✓ Experienced & Dedicated Faculty
✓ Personal Attention
✓ Printed Notes & Regular Tests
✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055
Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
• Std. XI & XII (Sci.)
• NEET
• JEE (Main & Advance)
• MHT-CET
• Polytechnic & Engg
• Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

विदेशी चंदे पर नियंत्रण और संतुलन की अपेक्षा

-ललित गर्ग

12 अगस्त 2026 का दिन भारतीय संसद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एफसीआरए विधेयक को लोकसभा ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति-जेपीसी के पास भेज दिया। यह फैसला केवल एक विधेयक को संसदीय प्रक्रिया के अगले चरण में भेजना नहीं है, बल्कि उस व्यापक बहस का अवसर है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी धन की पारदर्शिता, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्वायत्तता, नागरिक समाज की भूमिका और लोकतांत्रिक अधिकार-सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। विधेयक को जेपीसी के पास भेजे जाने से सरकार और विपक्ष के बीच तत्काल टकराव को कुछ हद तक विमर्श में बदलने का अवसर मिला है। एफसीआरए का इतिहास भी इस बहस की गंभीरता को समझने में मदद करता है। विदेशी धन के माध्यम से देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बाहरी प्रभाव की आशंकाओं को देखते हुए 1976 में पहली बार कानून बनाया गया था। वर्ष 2010 में इसे नए एफसीआरए कानून से प्रतिस्थापित किया गया और उसके बाद 2020 सहित विभिन्न चरणों में इसके प्रावधान अधिक कठोर होते गए। आज यह कानून केवल विदेशी चंदे की प्राप्ति और उसके उपयोग का लेखा-जोखा रखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े विमर्श का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

आंकड़े इस विषय की व्यापकता बताते हैं। पीआरएस के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक 14,449 एफसीआरए प्रमाणपत्र सक्रिय थे, जबकि 22,498 रद्द और 15,212 समाप्त माने गए। 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को लगभग 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान मिला। इन आंकड़ों को देखकर यह सवाल स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग कहां, किस उद्देश्य से और किस स्तर की निगरानी के साथ हुआ? लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है-क्या किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाना अपने आप में किसी वित्तीय या आपराधिक अनियमितता का प्रमाण माना जा सकता है? सरकार के अपने स्पष्टीकरण के अनुसार भी पंजीकरण समाप्त होने के कई कारण हो सकते हैं और हर समाप्ति को गलत काम से जोड़ना उचित नहीं है। यहीं से प्रस्तावित संशोधन का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। विधेयक में नामित प्राधिकरण की व्यवस्था प्रस्तावित है। यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है, वह स्वयं पंजीकरण छोड़ देती है या उसका प्रमाणपत्र नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियां पहले अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण के अधीन आ सकती हैं। यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल नहीं होता तो संपत्तियां स्थायी रूप से निहित की जा सकती हैं तथा उन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग या बेचने का प्रावधान है। बिक्री से प्राप्त राशि और अप्रयुक्त विदेशी अंशदान भारत की समेकित निधि में जमा किए जाने का प्रस्ताव है।

भारत में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विदेशी वित्तपोषण के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं अथवा राष्ट्रीय हित से टकराने वाली गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं। इसलिए एफसीआरए का मूल उद्देश्य-विदेशी अंशदान को पारदर्शी, उत्तरदायी और वैध उद्देश्यों तक सीमित रखना-न तो अनुचित है और न ही लोकतंत्र विरोधी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और प्रशासनिक शक्ति के विस्तार के बीच एक स्पष्ट रेखा भी होनी चाहिए। यही इस विधेयक की असली परीक्षा है। यदि किसी संस्था ने विदेशी धन का इस्तेमाल आतंकवाद, हिंसा, अलगाववाद, जबरन या प्रलोभन आधारित धर्मांतरण, राजनीतिक अस्थिरता अथवा भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किया है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रहित में ऐसी कठोरता आवश्यक है। मगर दूसरी ओर यदि कोई संस्था अस्पताल चला रही है, गरीबों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा रही है, पर्यावरण संरक्षण कर रही है, महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही है अथवा प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचा रही है, तो केवल तकनीकी या प्रक्रियागत चूक के कारण उसके वर्षों के सामाजिक कार्य और विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर तत्काल सरकारी नियंत्रण स्थापित हो जाना चिंता का विषय बन सकता है। यही कारण है कि जेपीसी के पास जाना इस विधेयक के लिए एक सकारात्मक अवसर है। संसद में बहुमत से कानून पारित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जिन कानूनों का प्रभाव हजारों संस्थाओं, लाखों लाभार्थियों और देश के व्यापक नागरिक समाज पर पड़ता हो, उनकी बारीकी से जांच लोकतंत्र को मजबूत करती है। जेपीसी में विपक्ष अपनी आपत्तियां रख सकता है, सरकार अपने तर्क स्पष्ट कर सकती है और विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, वित्तीय विशेषज्ञों तथा सुरक्षा एजेंसियों के अनुभवों को भी सामने लाया जा सकता है।

विधेयक में एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी प्रावधान यह भी है कि धार्मिक स्थल की धार्मिक प्रकृति को बनाए रखना अनिवार्य होगा। नामित प्राधिकरण किसी ऐसे स्थल को दूसरे उद्देश्य में बदल या उसकी धार्मिक प्रकृति समाप्त नहीं कर सकेगा। इसके अलावा प्रभावित संस्था को 90 दिनों के भीतर पुनरीक्षण का अधिकार और जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील का प्रावधान दिया गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि पंजीकरण बहाल होने पर अस्थायी रूप से निहित संपत्तियां और अप्रयुक्त धन वापस किए जाएंगे। ये प्रावधान स्वागत योग्य हैं, लेकिन सवाल यह रहेगा कि इन अधिकारों की वास्तविक स्वतंत्रता और प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन नवीनीकरण से जुड़ा है। 2026 के नियमों में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये विदेशी अंशदान के उपयोग को सक्रिय संस्था की पहचान के रूप में रखा गया है। साथ ही गतिविधि और राज्य-विशिष्ट पंजीकरण तथा अधिक विस्तृत उपयोग संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था निष्क्रिय संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जेपीसी को यह भी देखना होगा कि क्या हर छोटी लेकिन वास्तविक सामाजिक संस्था के लिए 10 लाख रुपये खर्च करना व्यावहारिक मानदंड है। सामाजिक उपयोगिता का मूल्य केवल धनराशि से नहीं किया जा सकता।

एफसीआरए की बहस को केवल सरकार बनाम विपक्ष या राष्ट्रवाद बनाम नागरिक स्वतंत्रता के द्वंद्व में सीमित करना भी उचित नहीं होगा। असली प्रश्न इससे कहीं बड़ा है-भारत विदेशी धन को किस तरह स्वीकार करेगा और यह सुनिश्चित कैसे करेगा कि विदेशी संसाधन भारतीय समाज के हित में काम करें, न कि भारत की नीतियों और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने का माध्यम बनें? इसी के साथ यह भी तय करना होगा कि सरकार की नियामक शक्ति इतनी व्यापक न हो जाए कि स्वतंत्र सामाजिक संस्थाओं की वैध असहमति भी संदेह की दृष्टि से देखी जाने लगे। भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र में नागरिक समाज सरकार का विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सहयोगी अंग है। हजारों गैर-सरकारी संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, दिव्यांग कल्याण और आपदा राहत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक संस्था को पारदर्शिता, लेखांकन और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमन का उद्देश्य संस्थाओं को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करना हो। संसद और जेपीसी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही संतुलन स्थापित करने की है। विदेशी चंदे की आड़ में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन सामाजिक सेवा की आड़ में यदि कहीं वित्तीय अनियमितता है तो उसके लिए भी कोई छूट नहीं होनी चाहिए। समान रूप से, वैध सामाजिक कार्य को केवल वैचारिक असहमति के कारण संदेह के घेरे में नहीं लाया जाना चाहिए। कानून ऐसा हो जिसमें अपराध पर कठोरता और वैध सामाजिक कार्य के प्रति संवेदनशीलता-दोनों साथ चलें।

एफसीआरए संशोधन विधेयक भारत की शासन-व्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर भी है। यदि जेपीसी इस बहस को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठाकर तथ्य, कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के संतुलन के आधार पर देखती है, तो यह विधेयक केवल विदेशी चंदे को नियंत्रित करने वाला कानून नहीं रहेगा, बल्कि भारत में पारदर्शी, उत्तरदायी और स्वस्थ नागरिक समाज की नई आधारशिला बन सकता है। अब अपेक्षा यह है कि जेपीसी न तो सरकारी कठोरता को आंख मूंदकर स्वीकार करे और न विपक्ष की आशंकाओं को अंतिम सत्य माने, बल्कि तथ्यों की गहराई में जाकर ऐसा संतुलित कानून सुझाए जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुरक्षित रहे, विदेशी धन भी पारदर्शी रहे और सामाजिक सेवा की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण रहे। यही एफसीआरए की वास्तविक कसौटी है-विदेशी धन पर नियंत्रण हो, लेकिन जनसेवा पर अंकुश नहीं।

सुरक्षा और अफवाहों के बीच सीमांत: अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का सच और सरकार की त्वरित कार्रवाई

अशोक भाटिया

अरुणाचल प्रदेश भारत का वह सुदूर पूर्वी मुकुट है, जिसकी भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व हमेशा से देश की सुरक्षा नीति के केंद्र में रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक हलकों से उठी चीनी सेना की 'धीमी घुसपैठ' की खबरों ने एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श को गरमा दिया है। एक ऐसे दौर में जब सीमा पर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, घुसपैठ की ऐसी खबरें न केवल रणनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, बल्कि आंतरिक मोर्चे पर भी असमंजस पैदा करती हैं। हालांकि, इस बार सरकार और भारतीय सेना ने न केवल इन दावों को पूरी तरह से निराधार और अफवाह करार दिया, बल्कि असाधारण सक्रियता दिखाते हुए स्थिति को तुरंत स्पष्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नेतृत्व में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा और उससे जुड़ी सूचनाओं के प्रति कितनी सजग और एक्शन मोड में है। अखबारों और मुख्यधारा के विमर्श के लिए यह केवल एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का गंभीर विश्लेषण करने का अवसर है कि आधुनिक दौर में सीमा सुरक्षा केवल अग्रिम चौकियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबरों की जड़ें 'पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल' की एक तथाकथित फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में खोजी जा सकती हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों और शिकारियों के पारंपरिक रास्तों पर कब्जा कर लिया है। इस दावे को हवा तब मिली जब सोशल मीडिया पर कुछ धुंधले और असत्यापित वीडियो प्रसारित होने लगे, जिनमें चीनी बुनियादी ढांचे और सैनिकों की उपस्थिति का दावा किया गया था। इस प्रकार की सूचनाएं जैसे ही सार्वजनिक पटल पर आईं, वैसे ही भारतीय सेना के शीर्ष कमान और देश के नीति-नियंताओं ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा कि सीमा पर भारत ने अपनी एक इंच जमीन भी नहीं खोई है। ऊपरी सुबनसिरी के दुर्गम इलाकों में स्थित सभी अग्रिम चौकियाँ पूरी तरह से भारतीय बलों के नियंत्रण में हैं। सेना ने स्पष्ट किया कि जिसे 'घुसपैठ' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वह असल में चीन द्वारा अपनी सीमा के भीतर किया जा रहा बुनियादी ढांचा विकास हो सकता है, जिसे जानबूझकर भारतीय क्षेत्र के भीतर दिखाकर सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया। सरकार का यह त्वरित और पारदर्शी रुख सराहनीय है, क्योंकि अक्सर सीमावर्ती मुद्दों पर आधिकारिक सूचनाओं में देरी अफवाहों को खाद-पानी देने का काम करती है।

इस विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारत और चीन के बीच हालिया कूटनीतिक और भौगोलिक घटनाक्रमों पर नजर डालना जरूरी है। भारत सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा कदम उठाते हुए अधिकारिक मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश की 27 प्रमुख जगहों के नाम पूरी तरह से भारतीय पहचान के अनुरूप दर्ज किए थे। यह कदम चीन के उस पुराने पैंतरे का सीधा जवाब था, जिसके तहत वह अरुणाचल के विभिन्न स्थानों का बार-बार 'पुनः नामकरण' कर

हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
मार्गदर्शन

उन्हें अपनी संप्रभुता का हिस्सा बताने की कोशिश करता रहा है। भारत के इस संप्रभु अधिकार और कड़े रुख से बीजिंग निश्चित रूप से असहज हुआ था। विदेश मंत्रालय ने इस मोर्चे पर हमेशा की तरह यह दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा; चीन की किसी भी कृत्रिम नामावली या काल्पनिक दावों से यह ऐतिहासिक और जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली है। इसलिए, जब भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली हो, तब देश के भीतर से ही सीमा सुरक्षा पर इस तरह के असत्यापित और कमजोर दावे उठना पूरी रक्षा रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे केवल स्थानीय स्तर का मामला नहीं माना, बल्कि देश की राजधानी में संसद भवन परिसर में रक्षा और विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाकर साफ संदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर सरकार की चौबीसों घंटे पैनी नजर है।

आज की दुनिया में सीमा की रक्षा केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं होती, बल्कि यह हाइब्रिड वॉरफेयर के युग में प्रवेश कर चुकी है। चीन इस रणनीति का पुराना खिलाड़ी है, जहां वह बिना एक भी गोली चलाए, भ्रामक सूचनाओं और मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए अपने विरोधी को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की कोशिश करता है। अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्र में चरवाहों के रास्तों को रोके जाने या धीमी घुसपैठ की अफवाहें इसी सूचना युद्ध का हिस्सा हो सकती हैं। सीमा पर रहने वाले नागरिकों और देश के आम मानस में डर और अविश्वास पैदा करना इस तरह की अफवाहों का मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय सेना ने इस खतरे को भांपते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी सोशल मीडिया नैरेटिव का शिकार न हों। सीमा पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और थल सेना के जवान न केवल आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं, बल्कि वे निगरानी के लिए उपग्रहों, ड्रोनों और अत्याधुनिक रडार प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में यह लगभग असंभव है कि कोई बड़ी या छोटी घुसपैठ हो और वह भारतीय रक्षा तंत्र की नजरों से बच जाए। सरकार का एक्शन इस बात का संकेत है कि वह इस सूचना युद्ध में बैकफुट पर रहने के बजाय आक्रामक तरीके से सच को सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर भारत की नीति में पिछले एक दशक में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अतीत की सरकारें अक्सर इस रक्षात्मक सोच के साथ काम करती थीं कि यदि सीमा के करीब बेहतर सड़कें और बुनियादी ढांचा बनाया गया, तो युद्ध की स्थिति में चीनी सेना उसका लाभ उठाकर भारतीय क्षेत्र में तेजी से प्रवेश कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इस पुरानी और पराजयवादी नीति को पूरी तरह से पलट दिया है। 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' के तहत अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा के सीमावर्ती गांवों का कायाकल्प किया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, रणनीतिक सुरंगे बनाई जा रही है और दूरदराज के इलाकों तक बिजली तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों का यह विकास केवल सेना के आवागमन को सुगम नहीं बनाता, बल्कि स्थानीय आबादी के पलायन को भी रोकता है। सीमा पर रहने वाले नागरिक हमारे 'प्रथम रक्षक' हैं। जब उनके पास बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षा होगी, तो वे किसी भी विदेशी पैंतरेबाजी का पहला और सबसे मजबूत प्रतिरोध बनेंगे। सरकार की इस चौतरफा विकास नीति ने चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने का काम किया है, जिससे बौखलाकर वह अक्सर सीमा पर तनाव पैदा करने या अफवाहों को हवा देने की कोशिश करता है। गौरतलब है कि इस घटना से मीडिया, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों के लिए कुछ गहरे सबक मिलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसे दलीय राजनीति और चुनावी लाभ-हानि से ऊपर रखा जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या क्षेत्रीय संगठन को बिना किसी ठोस और आधिकारिक प्रमाण के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के दावे करने से बचना चाहिए। ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान न केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को कमजोर करते हैं, बल्कि शून्य से नीचे के तापमान में देश की रक्षा कर रहे जवानों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे 'सनसनी' और 'क्लिकबेट' की दौड़ से बाहर निकलकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरों का कड़ा फैक्ट-चेक करें। सरकार ने इस मामले में जिस तरह से तत्परता दिखाई, वह भविष्य के लिए एक मानक तय करती है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच का यह समन्वय ही भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। अरुणाचल प्रदेश में शांति और सुरक्षा पूरी तरह से कायम है, और सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया है कि नए भारत की सीमाओं की सुरक्षा अभेद्य है और किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को पनपने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एटम बम का गहना पहने पाकिस्तान, तालीम और रोजगार से क्यों महरूम?

-रामकेश एम. यादव 'सरस'

पाकिस्तान आज एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। 1947 से पहले आज का पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था और सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख़्तूनख़्वा तथा दूसरे क्षेत्रों का इतिहास इस उपमहाद्वीप की साझा सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक विरासत से जुड़ा रहा है। विभाजन ने राजनीतिक सीमाएँ बदल दीं, मगर सदियों के सांस्कृतिक रिश्ते, भाषाएँ, लोकपरंपराएँ और इंसानी स्मृतियाँ किसी एक दिन में समाप्त नहीं हो सकतीं। आज भारत और पाकिस्तान अलग-अलग संप्रभु राष्ट्र हैं और दोनों के अपने राष्ट्रीय हित हैं, लेकिन सीमा के दोनों ओर रहने वाले आम लोगों की मूल जरूरतें बहुत अलग नहीं हैं। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, हर नौजवान चाहता है कि उसे काम मिले, हर किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाए और हर परिवार अमन तथा सम्मान के साथ जीवन बिताए लेकिन पाकिस्तान की आज की तस्वीर केवल इतिहास और साझा संस्कृति की तस्वीर नहीं है। वहाँ की जमीन पर एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई देती है–महँगाई से परेशान परिवार, बेरोजगार नौजवान, शिक्षा से बाहर बच्चे, इलाज के लिए परेशान गरीब, असुरक्षा में जीते नागरिक, आतंकवाद की घटनाओं से सहमे हुए इलाके और ऐसे प्रांत जहाँ केंद्र और स्थानीय आबादी के बीच अविश्वास लगातार गहराता दिखाई देता है। एक तरफ पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों को अपनी सामरिक शक्ति का प्रतीक मानता है, दूसरी तरफ उसका आम नागरिक रोटी, रोजगार, शिक्षा, मकान और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। टी. व्ही चैनल पर हम देख -देख के बहुत दुखित होते हैं।

महँगाई की मार गरीब आदमी को सबसे पहले उसकी रसोई में महसूस होती है। जब पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, दाल, सब्जी, दूध और रोजमर्रा की दूसरी वस्तुएँ महँगी होती हैं, तो परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। आम आदमी के पास आमदनी बढ़ाने का रास्ता उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, जितनी तेजी से खर्च बढ़ जाता है। बाजार में सामान देखकर गरीब आदमी को यह सोचना पड़ता है कि आज क्या खरीदे और क्या छोड़ दे। बच्चों की फीस दे या घर का राशन लाए, दवा खरीदे या बिजली का बिल भरे, किराया दे या घर के दूसरे खर्च पूरे करे–ऐसी परिस्थितियाँ किसी भी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।गरीबी केवल खाली जेब का नाम नहीं है। गरीबी वह स्थिति है जिसमें इंसान अपनी इच्छा होते हुए भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, बीमारी आने पर अच्छे अस्पताल तक नहीं पहुँच पाता, अपना घर बनाने का सपना वर्षों तक टालता रहता है और बेरोजगार बेटे-बेटी की शादी के बारे में सोचकर भी घबरा जाता है। जब घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसा न हो, किराया लगातार बढ़ता रहे और रोजमर्रा का खर्च ही मुश्किल से पूरा हो, तब नौजवान परिवार बसाने के बजाय पहले रोजगार और रहने की जगह तलाशता है। इस तरह आर्थिक संकट धीरे-धीरे व्यक्ति के निजी जीवन, परिवार और समाज तक पहुँच जाता है। पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर भी चिंता पैदा करती है। उपलब्ध आकलनों के अनुसार लगभग ढाई करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं।

यह संख्या केवल एक आँकड़ा नहीं है; इसके पीछे करोड़ों अधूरे बचपन छिपे हैं। कोई बच्चा गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाता, कोई दूरदराज के इलाके में विद्यालय की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित रहता है, किसी परिवार के लिए फीस, किताब, वर्दी और आने-जाने का खर्च भारी पड़ता है। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से बाहर हों, वहाँ परमाणु शक्ति का गौरव अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मानवीय विकास का सवाल उससे कहीं बड़ा हो जाता है। जिस बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए, अगर उसके हाथ में मजदूरी का औजार आ जाए, तो यह केवल उस बच्चे की हार नहीं है; यह पूरे राष्ट्र के भविष्य की हार है। तालीम इंसान को केवल नौकरी नहीं देती, वह सोचने की ताकत देती है। शिक्षा से बच्चा विज्ञान समझता है, तकनीक सीखता है, अपने अधिकार पहचानता है और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने योग्य बनता है। यदि पाकिस्तान को आनेवाली पीढ़ियों को मजबूत करना है तो

हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
मार्गदर्शन

विद्यालयों, शिक्षकों, तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को प्राथमिकता देनी होगी लेकिन पाकिस्तान की समस्या केवल गरीबी और शिक्षा तक सीमित नहीं है। उसके कई प्रांतों की अपनी अलग-अलग गंभीर समस्याएँ हैं। बलूचिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन, राजनीतिक असंतोष और राज्य के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है। 2026 में भी वहाँ अलगाववादी हिंसा के बड़े हमले हुए हैं। जनवरी के अंत में बलूचिस्तान में समन्वित हमलों में नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई, जबकि वर्ष के दौरान रेल हमलों और अन्य हिंसक घटनाओं ने स्थिति की गंभीरता को फिर सामने रखा।

बलूचिस्तान की समस्या को केवल बंदूक और सैन्य अभियान से समझना पर्याप्त नहीं है। वहाँ के लोगों की शिकायतों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों में हिस्सेदारी, विकास, रोजगार और नागरिक अधिकारों से जुड़े सवाल भी समझने होंगे। यदि किसी प्रांत के लोगों में यह भावना पैदा हो कि उनके प्राकृतिक संसाधनों से देश को लाभ मिलता है लेकिन उनके अपने इलाकों में पर्याप्त विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं पहुँचतीं, तो असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। बंदूक उस असंतोष को और हिंसक बना सकती है, लेकिन उसके मूल सामाजिक और राजनीतिक सवालों का समाधान केवल बंदूक से नहीं होता। बलूचिस्तान में हिंसा का दूसरा चेहरा आम नागरिक है। जब सड़कें असुरक्षित हों, बाजार भय में हों, ट्रेन पर हमला हो, सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच मुठभेड़ हो और नागरिक मारे जाएँ, तो सबसे अधिक कीमत सामान्य परिवार चुकाता है। जुलाई में पाकिस्तान में आतंकवादी हिंसा को लेकर जारी रिपोर्टों में बड़ी संख्या में मौतें दर्ज की गईं और नागरिकों की मौतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि बताई गई। सवाल यह है कि जिस देश के नागरिक अपनी जान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हों, वहाँ विकास की योजनाएँ किस गति से आगे बढ़ेंगी? खैबर पख़्तूनख़्वा की स्थिति भी अलग नहीं है। वहाँ पाकिस्तान तालिबान और दूसरे उग्रवादी समूहों से जुड़ी हिंसा ने लंबे समय से सामान्य जीवन को प्रभावित किया है। अगस्त के आरंभ में स्वात में एक शांति रैली पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें लोग मारे गए और बड़ी संख्या में घायल हुए। यह विडंबना कितनी भयावह है कि जिन लोगों को अपने इलाके में शांति चाहिए, उन्हें भी हिंसा का निशाना बनना पड़े। हाल की घटनाएँ बताती हैं कि पाकिस्तान के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में सुरक्षा संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है।

परमाणु हथियार सामरिक शक्ति का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन किसी देश की स्थायी शक्ति उसके शिक्षित, स्वस्थ और रोजगारयुक्त नागरिकों से बनती है। मिसाइल सीमा की रक्षा कर सकती है, लेकिन बेरोजगार नौजवान को रोजगार नहीं दे सकती। गोला-बारूद युद्ध में काम आ सकता है, लेकिन गरीब परिवार की रसोई नहीं चला सकता। परमाणु बम दुश्मन को डराने की क्षमता रख सकता है, लेकिन स्कूल से बाहर बच्चे को किताब नहीं दे सकता। अस्पताल का निर्माण, विश्वविद्यालय की स्थापना, कारखाने का निर्माण और रोजगार का अवसर भी राष्ट्र निर्माण के उतने ही महत्वपूर्ण साधन हैं जितने सुरक्षा के दूसरे साधन। इसका अर्थ यह नहीं कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा छोड़ दे। ऐसा कहना भी वास्तविकता से दूर होगा। अर्थ यह है कि सुरक्षा और मानवीय विकास के बीच संतुलन बनाया जाए। यदि सुरक्षा के नाम पर नागरिक विकास लगातार पीछे जाता रहा, तो अंततः वही कमजोर नागरिक और कमजोर अर्थव्यवस्था देश की सुरक्षा को भी कमजोर करेंगे। पाकिस्तान को अपने प्रांतों के साथ भी भरोसे का रिश्ता मजबूत करना होगा। बलूचिस्तान के असंतोष को केवल विद्रोह मानकर दबा देना पर्याप्त नहीं; वहाँ विकास, राजनीतिक भागीदारी, संसाधनों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी और नागरिक अधिकारों के सवालों पर भी गंभीरता से काम करना होगा। खैबर पख़्तूनख़्वा में आतंकवाद से लड़ने के साथ-साथ युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के रास्ते खोलने होंगे। सिंध के गरीब ग्रामीण इलाकों में पानी, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएँ मजबूत करनी होंगी। पंजाब में भी विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। किसी देश के हर प्रांत को यह भरोसा होना चाहिए कि वह राष्ट्र का बराबर का हिस्सा है। जब नागरिक को लगता है कि उसके साथ बराबरी का व्यवहार हो रहा है, उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और उसकी आवाज सुनी जाती है, तब राष्ट्र मजबूत होता है। जब किसी क्षेत्र में लगातार उपेक्षा, हिंसा या अविश्वास की भावना बढ़ती है, तो राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है। यदि पाकिस्तान में आतंकवाद घटता है, शिक्षा बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है और गरीबी कम होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ पड़ेगा। पाकिस्तान को यह तय करना होगा कि आनेवाली पीढ़ियों को कैसी विरासत देनी है। ऐसी विरासत जिसमें परमाणु हथियार तो हों लेकिन करोड़ों बच्चे शिक्षा से बाहर हों? ऐसी व्यवस्था जिसमें मिसाइलें हों लेकिन गरीब परिवार के पास पक्का घर न हो? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बड़े-बड़े सुरक्षा खर्च हों लेकिन बेरोजगार युवा शादी और घर बसाने के बारे में सोचकर परेशान हो? या ऐसी व्यवस्था जिसमें सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनें? होना तो ये चाहिए कि हर हाथ को काम मिले। हर बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए। हर बीमार को अस्पताल मिलना चाहिए। हर किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हर परिवार को सुरक्षित घर और सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। हिंदू, ईसाई, सिख या किसी भी अल्पसंख्यक नागरिक को अपने धर्म और पहचान के कारण भय में नहीं जीना चाहिए।

बलूचिस्तान के नागरिक हों या खैबर पख़्तूनख़्वा के, सिंध के गाँव हों या पंजाब के कस्बे–हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि देश उसका भी उतना ही है जितना किसी शक्तिशाली वर्ग का। पाकिस्तान की वास्तविक ताकत उसके परमाणु बम में नहीं, उसके करोड़ों लोगों में है। किसान की मेहनत, मजदूर का पसीना, शिक्षक की कलम, डॉक्टर की सेवा, वैज्ञानिक की खोज, कलाकार की रचना और नौजवान का हुनर–यही किसी देश की स्थायी शक्ति है। एटम बम सुरक्षा दे सकता है, लेकिन शिक्षा भविष्य देती है। मिसाइल सीमा की रक्षा कर सकती है, लेकिन रोजगार परिवार की रक्षा करता है। गोला-बारूद युद्ध लड़ सकता है, लेकिन अस्पताल जीवन बचाता है और किसी भी देश की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब उसका गरीब नागरिक भी यह कह सके कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी संभावना है। बारूद से आगे बढ़कर किताब की ओर, भय से आगे बढ़कर भरोसे की ओर, बेरोजगारी से आगे बढ़कर रोजगार की ओर, गरीबी से आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता की ओर और केवल सामरिक शक्ति से आगे बढ़कर मानवीय शक्ति की ओर। पाकिस्तान मजबूत हो–लेकिन केवल हथियारों से नहीं; अपने नागरिकों को शिक्षित करके, हर हाथ को काम देकर, गरीब को सम्मान देकर, अस्पतालों को मजबूत करके, किसानों को समृद्ध करके, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देकर और अपने सभी प्रांतों को बराबरी का अधिकार और अवसर देकर। यही वास्तविक राष्ट्रनिर्माण है। यही वह शक्ति है जिसे कोई मिसाइल नष्ट नहीं कर सकती।

आजादी के अमृतकाल में पत्रकारों की नई आस

-सुरेश गांधी

स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय उत्सव नहीं होता, वह समाज के उन वर्गों की आकांक्षाओं का भी दर्पण होता है जो लोकतंत्र की निरंतरता के लिए मौन किंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वर्ष आजादी के जश्न के बीच उत्तर प्रदेश के पत्रकार समुदाय में एक नई उम्मीद जागी है। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात और उसके बाद सूचना विभाग स्तर पर हुई चर्चा ने वर्षों से लंबित पत्रकार कल्याण के प्रश्न को फिर सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। लखनऊ में हुई इस मुलाकात में स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री रविन्द्र जायसवाल के साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्रकारों की समस्याओं से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का स्वर किसी विशेष क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकार समाज की सामूहिक पीड़ा का था। मुख्यमंत्री ने विषय को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। इसके बाद मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी और सचिव भारत सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना निदेशक विशाल सिंह से मिलकर मांगों को विस्तार से रखा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख प्रश्न पत्रकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा का था। कभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार, दवाएं और चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त थीं। रेल यात्रा में भी रियायतें और विशेष सुविधाएं उपलब्ध थीं। समय के साथ ये व्यवस्थाएं समाप्त होती चली गईं। आज जिले और तहसील स्तर पर कार्यरत अनेक पत्रकार सीमित आय में जीवनयापन करते हैं। बीमारी, दुर्घटना या आकस्मिक संकट उनके लिए आर्थिक आपदा बन जाता है। सहायता मिल भी जाए तो वह दया का विषय बनती है, जबकि पूर्व की व्यवस्था अधिकार आधारित थी।

पत्रकार प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य सुविधा की पुनर्बहाली के साथ आयुष्मान जैसी व्यापक चिकित्सा सुरक्षा, पत्रकार पेंशन योजना, आवास योजना, दुर्घटना एवं जीवन बीमा, पत्रकार सुरक्षा आयोग, जिला स्तर पर हेल्प डेस्क और आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों के लिए विशेष सहायता कोष की मांग की है। यह केवल सुविधाओं की सूची नहीं, बल्कि पत्रकारिता को गरिमामय कार्य-परिस्थिति देने का आग्रह है।

इसी संदर्भ में ह्लएक देश, एक पत्रकारह्व की अवधारणा भी उल्लेखनीय है। यदि पत्रकारों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और पहचान संबंधी मानक पूरे देश में एक समान हों, तो विभिन्न राज्यों में कार्यरत पत्रकारों को अधिकार प्राप्त करने में अनावश्यक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज पत्रकारिता का कार्यक्षेत्र जिला या राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल युग में पत्रकार राष्ट्रीय परिदृश्य का हिस्सा है; इसलिए उसकी मूलभूत सुरक्षा भी व्यापक दृष्टि से देखी जानी चाहिए। लोकतंत्र में पत्रकार

केवल समाचार लिखने वाला व्यक्ति नहीं होता। वह समाज की आवाज को शासन तक पहुंचाने वाला सेतु है। प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो, अपराध हो या जनसमस्या–सबसे पहले वही घटनास्थल पर उपस्थित दिखाई देता है। विडंबना यह है कि जनहित के प्रश्न उठाने वाला यह वर्ग स्वयं स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण के प्रश्नों से जूझता रहता है।

आज जब उत्तर प्रदेश विकास, निवेश और सामाजिक कल्याण के नए अध्याय लिखने का दावा कर रहा है, तब पत्रकार कल्याण पर पुनर्विचार समय की मांग है। यदि सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा, पेंशन, आवास और सुरक्षा आयोग जैसी मांगों पर ठोस निर्णय लेती है, तो यह केवल पत्रकारों को राहत देने वाला कदम नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती का संकेत भी होगा।

आजादी के अमृतकाल में सबसे बड़ी आशा यही है कि संवाद की यह पहल घोषणा तक सीमित न रहे। पत्रकारों की अपेक्षा किसी विशेषाधिकार की नहीं, बल्कि सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा की है। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात ने उम्मीद का दीप जलाया है; अब प्रदेश की पत्रकारिता उस दीप को नीति और निर्णय की स्थायी रोशनी में बदलते देखने की प्रतीक्षा कर रही है।

स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के बीच यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पत्रकार इसे केवल सुविधा नहीं, बल्कि गरिमामय कार्य-परिस्थिति और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया और सूचना विभाग स्तर पर हुई आगे की बातचीत ने प्रदेश के पत्रकार समुदाय में यह विश्वास जगाया है कि वर्षों से लंबित मांगों पर अब ठोस पहल संभव है। प्रदेश भर के पत्रकार संगठनों की नजर अब सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यदि स्वास्थ्य, पेंशन, आवास और सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर निर्णय होता है तो इसे उत्तर प्रदेश के पत्रकार कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा. उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस विषय पर सकारात्मक पहल करेगी और पत्रकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा को पुनः नीतिगत प्राथमिकता देगी।

दहिसर के वरिष्ठ समाजसेवी हरिश्याम विश्वकर्मा का आकस्मिक निधन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। दहिसर के वरिष्ठ समाजसेवी हरिश्याम राममूरत विश्वकर्मा का 13 अगस्त 2026 को 66 वर्ष की उम्र में आकस्मिक निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से दहिसर सहित विश्वकर्मा समाज में शोक की लहर छा गई है। स्वर्गीय हरिश्याम राममूरत विश्वकर्मा का जन्म 6 दिसंबर 1961 को हुआ था। वे मूल रूप से भैंसा ,चंदवक केराकत जिला जौनपुर के निवासी थे। वे एक मिलनसार, सरल एवं समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। वे विश्वकर्मा हाई स्कूल के संचालक भी थे और शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे।उनके निधन से परिवार, समाज, मित्रों एवं शुभचिंतकों को गहरा आघात पहुंचा है। परिवार के लिए यह अत्यंत दुखद समय है।इससे पहले उनके छोटे भाई के निधन का दुख भी परिवार झेल चुका है। शोकाकुल परिवार में रवि विश्वकर्मा, भारत विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा, ऋषि विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा (पप्पू) दीपू, गप्पू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लालता विश्वकर्मा, धनश्याम विश्वकर्मा सहित समस्त विश्वकर्मा परिवार एवं परिजन शामिल हैं। इस दुखद घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने वालों में समरस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ किशोर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे, पत्रकार शिवशंकर तिवारी, पत्रकार रोहित जायसवाल, सुरेंद्र पांडे, राजेश, संतोष मिश्रा ,आनंद मिश्रा, भैयालाल गौड़, शंकर गुप्ता, मदन गुप्ता, प्रभात मिश्रा, मानिकचंद यादव, गुरु मुकुंद शर्मा, भोला वर्मा, पूरव गांधी,रतिलाल अशोक मिश्रा, वैभव मिश्रा समेत अनेक समाजसेवी, पत्रकार, मित्र एवं शुभचिंतक शामिल हैं।

दीप अमावस्या पर प्राथमिक स्कूल में दीप प्रकल्प कार्यक्रम

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। आषाढ़ अमावस्या यानी दीप अमावस्या के अवसर पर जनरल एज्युकेशन इंस्टीट्यूट के भिवंडी स्थित पूर्व प्राथमिक विद्यालय में दीप प्रकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों से परिचित कराया गया। इस अवसर पर अभिभावकों ने विद्यार्थियों के साथ पारंपरिक दीप विद्यालय भेजे। विद्यालय की मुख्याध्यापिका अनिता सुतार, सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष शाम तुकाराम सिंघासणे और श्यामली सिंघासणे विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों एवं शिक्षकों ने आटे से बनाए गए पारंपरिक दीपों से विद्यार्थियों का औक्षण किया। इस पहल के माध्यम से विद्यालय ने विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का संदेश दिया।

जारो एजुकेशन ने वित्त वर्ष 27 की शानदार शुरूआत की

मुंबई। जारो एजुकेशन ने उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल अपस्किलिंग की बढ़ती मांग के दम पर वित्त वर्ष 27 की मजबूत शुरूआत की है। इस दौरान कंपनी ने राजस्व में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज की है और मुनाफे में बड़ा सुधार देखने को मिला है। इस तिमाही में कंपनी ने अपने संस्थानों से जुड़े नेटवर्क को मजबूत किया, नई टेक्नोलॉजी-आधारित शिक्षण क्षेत्रों में विस्तार किया, और अपने कॉरपोरेट लर्निंग बिजनेस में तेजी लाई। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में कुल आय 7,262.99 लाख रुपये रही, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के 6,081.59 लाख रुपये की तुलना में 19.43% अधिक है। परिचालन से राजस्व पिछले साल के 6,067.46 लाख रुपये से बढ़कर 7,075.05 लाख रुपये हो गया। एबिटा में सालाना आधार पर 20.89% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 1,704.20 लाख रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का टैक्स के बाद (पीएटी) लाभ 48.27% बढ़कर 1,116.89 लाख रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 753.30 लाख रुपये था। पीएटी मार्जिन पिछले साल के 12.39% से सुधरकर 15.38% हो गया, जो दिखाता है कि कंपनी का कारोबार जैसे-जैसे बढ़ रहा है, उसकी कमाई करने की क्षमता भी बेहतर हो रही है। शिक्षार्थियों के लगातार जुड़ाव के बल पर जारो एजुकेशन ने इस तिमाही में 19,030 लाख रुपये की ग्रॉस बुकिंग दर्ज की और 8,169 नए प्रवेश हासिल किए (6,979 डिग्री और 1,190 सर्टिफिकेशन)। प्रति शिक्षार्थी औसत कमाई 4.5% बढ़कर ?86,609 हो गई, जो उच्च मूल्य वाले पाठ्यक्रमों की मजबूत मांग को दशार्ती है। एआई और तकनीक के कारण तेजी से बदलते स्किल्स के इस दौर में अब लगातार सीखते रहना जरूरी हो गया है। यह बदलाव जारो एजुकेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है।

धोडीपाडा में अंतिम संस्कार मार्ग पर पुल का इंतजार, निधि के अभाव में काम अटका

पालघर(उत्तरशक्ति)। धुंदलवाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत धोडीपाडा में अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले मार्ग पर पुल निर्माण का मामला निधि के अभाव में लंबित है। इस संबंध में प्रकाशित समाचार के बाद जिला परिषद के निर्माण विभाग ने मौके का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। निर्माण विभाग के अनुसार धुंदलवाड़ी-खड़कीपाड़ा में श्मशानभूमि स्थित है। धोडीपाड़ा के ग्रामीणों के लिए श्मशानभूमि तक पहुंचने के लिए करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा खड़ीकरण किया हुआ रास्ता उपलब्ध है। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीण पारंपरिक रूप से नाले के बीच से रास्ता बनाकर श्मशानभूमि तक पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में इस मार्ग से आवागमन में विशेष परेशानी होने की बात सामने आई है। धोडीपाड़ा की आबादी करीब 130 से 150 है। ग्रामीणों की मांग है कि अंतिम संस्कार के समय आवागमन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए नाले पर पुल का निर्माण किया जाये। निर्माण विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए करीब एक करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वर्तमान में पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण पुल का निर्माण कार्य लंबित है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निधि उपलब्ध होने के बाद आवश्यक प्रक्रिया के तहत इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन द्वारा आवश्यक निधि उपलब्ध कराकर पुल निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जायेगा।

विकसित भारत-रोजगार व आजीविका हमी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पालघर में पंच संमेलन

पालघर(उत्तरशक्ति)। विकसित भारत-रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कानून-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश से पालघर जिला परिषद के बिरसा मुंडा सभागार में 12 अगस्त को जिला स्तरीय पंच संमेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। संमेलन में तहसील स्तरीय सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक तथा क्लर्क-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटरों को अभियान के उद्देश्यों, पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। उप जिला कार्यक्रम समन्वयक (V B G RAM G) अतुल पारसकर ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP), परिवार पंजीकरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, विकास कार्यों की योजना एवं क्रियान्वयन, विभिन्न योजनाओं का अभिसरण, पारदर्शिता, शिकायत निवारण तथा सामाजिक लेखापरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिला स्तरीय पंच संमेलन के बाद 15 अगस्त 2026 तक तहसील स्तर पर भी पंच संमेलन आयोजित किये जायें। इन संमेलन में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। तहसील स्तरीय संमेलन में कानून के उद्देश्यों, जनप्रतिनिधियों की भूमिका, विकसित ग्राम पंचायत योजना तथा विभिन्न योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर मार्गदर्शन किया जायेगा। इससे पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका के अवसर एवं विकास कार्यों को अधिक गति मिलने की उम्मीद है।

उत्तर क्षेत्रीय संस्था ने बोईसर के नये डीवाईएसपी दिनेश बैसाने का किया सत्कार

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। बोईसर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी (डीवाईएसपी) के रूप में दिनेश बैसाने ने पदभार संभाल लिया है। उनके पदभार ग्रहण करने पर उत्तर क्षेत्रीय संस्था की ओर से उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों ने बोईसर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग का भरोसा दिलाया। डीवाईएसपी दिनेश बैसाने ने स्वागत के लिए संस्था के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए हरसंभव प्रयास करने की बात कही। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अरविंद सिंह क्षत्रिय के नेतृत्व में सज्जन लाल (लालाभाई) गुप्ता, हनुमान सिंह, अमर सिंह, रामनरेश यादव सहित अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने डीवाईएसपी दिनेश बैसाने से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

जन्मदिन पर किया वृक्षारोपण व खाद्य सामग्री वितरित

पालघर(उत्तरशक्ति)। अनुश्री फाउंडेशन की सचिव पुष्पा तिवारी के सुपुत्र अंशु तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए वृक्षारोपण एवं बच्चों को बिस्किट इत्यादि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम चिराग विद्यालय, भीमनगर, बोईसर (पालघर) में संपन्न हुआ।

जन्मदिन के अवसर पर विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा बच्चों को बिस्किट इत्यादि वितरित किये गये। अनुश्री फाउंडेशन की सचिव पुष्पा तिवारी ने कहा कि जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों को सामाजिक एवं पर्यावरण हित के कार्यों से जोड़कर मनाने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और बच्चों में भी प्रकृति के प्रति प्रेम एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। इस अवसर पर उमेश सोनार सहित अन्य उपस्थित लोगों ने पौधारोपण में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। उपस्थित लोगों ने अंशु तिवारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मानखुर्द के वीर जीजा माता मार्ग संकल्प वसाहत में गंदगी का साम्राज्य

मुंबई (उत्तरशक्ति)। एक तरफ केंद्र तथा राज्य सरकार जहां पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाए हुए है वहीं दूसरी तरफ मानखुर्द के वीर जीजा माता मार्ग संकल्प वसाहत करबला चाल में गंदगी के अलावा रास्तों की हालत खस्ता बनी हुई है। बरसात के इस मौसम में यहां जगह जगह पानी भरने से आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।खास बात यह है कि २० साल पूर्व बसी इस झोपड़पट्टी में आज भी नागरिक सुविधाओं का अभाव है। जिसके कारण यहां के नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी पारधी महासंघ मुंबई व नवी मुंबई के अध्यक्ष संतोष एकनाथ पवार ने स्थानीय नगरसेवक नवनाथ बन से यहां रास्ता और पानी निकासी के लिए नाली बनाने की मांग की है।

मिली जानकारी के अनुसार मानखुर्द के वीर जीजा माता मार्ग संकल्प वसाहत २० साल पूर्व ट्रांजिट कैंप के नाम से बसाई गई थी। अधिकांश लोग रेल पटरियों के किनारे से यहां पुनर्वासित किए गए हैं। यहां ९०० के आसपास झोपड़े है। जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। लेकिन इस झोपड़पट्टी में आज भी रास्ते और पानी निकासी नालियों का अभाव है। आदिवासी पारधी महासंघ मुंबई व नवी मुंबई के अध्यक्ष संतोष एकनाथ पवार ने इस झोपड़पट्टी का दौरा करते हुए बताया कि मनपा द्वारा इस झोपड़पट्टी की साफ सफाई न किए जाने से यहां कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से यहां बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। दूसरी खास बात यह है कि यहां ऊबड़ खाबड़ रास्तों को आज तक नहीं बनाया गया। जिसके कारण बरसात के मौसम में इन रास्तों पर पानी जमा होने से स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। संतोष एकनाथ पवार ने स्थानीय नगरसेवक नवनाथ बन से यहां पानी निकासी के लिए नालिया और रास्तों को बनाने की मांग की है।

भिवंडी-ठाणे बायपास पर गड्ढों का साम्राज्य, आदित्य ठाकरे की वीडियो पोस्ट से फिर उठा सड़क की बदहाली का मुद्दा

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। मुंबई-नासिक महामार्ग से जुड़े भिवंडी-ठाणे बायपास मार्ग पर इन दिनों बड़े-बड़े गड्ढों का साम्राज्य बना हुआ है। सड़क की खराब हालत और अधूरे निर्माण कार्यों के कारण वाहन चालकों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। भिवंडी-ठाणे बायपास के आठ लेन के विस्तार का काम वर्ष 2018 से जारी है, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण आज भी इस मार्ग पर यातायात की समस्या बनी हुई है। सड़क पर कई फ्लाईओवर का काम अधूरा है, जबकि कंक्रीटीकरण का काम भी लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में जगह-जगह पड़े गड्ढों ने वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ा दी है। बतादें कि इसी मार्ग से गुजरते समय शिवसेना नेता एवं पूर्व मंत्री तथा विधायक आदित्य ठाकरे को भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। उन्होंने सड़क की बदहाली और यातायात की स्थिति का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ह्यएक्सह्ल पर पोस्ट किया। इसके बाद भिवंडी-ठाणे बायपास की खराब स्थिति एक बार फिर चर्चा में आ गई है। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण और विस्तार का काम जारी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। अब नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें इस सड़क के पूरी तरह तैयार होने और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए और कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा।

15 अगस्त की ग्रामसभा में घरकुल समेत विभिन्न विकास कार्यों पर होगी चर्चा

महिलाओं और ग्रामीणों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आहवान

पालघर (उत्तरशक्ति)। 15 अगस्त 2026 को जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्रामसभा में ग्रामीणों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गांव के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय सहभागिता दर्ज कराने का आहवान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने किया है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत घरकुल की प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पर ग्रामसभा में चर्चा की जायेगी। ग्रामसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List-PWL) को अंतिम रूप देने का विषय रखा जायेगा। इस अवसर पर आवास प्लस 2024 के तहत तैयार की गई मसौदा प्रतीक्षा सूची (Draft PWL) ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। घरकुल योजना के अलावा ग्रामसभा में VB-GRAM G अभियान, विकसित ग्राम पंचायत योजना, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का स्कूलों में पंजीकरण, विद्यालयों की मूलभूत सुविधाएं, आदिवासी विकास योजनाएं, मेरा गांव, स्वास्थ्य संपन्न गांव अभियान सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए ग्रामसभा में इस अधिनियम का वाचन करने के निर्देश भी दिए गये हैं। ग्रामसभा के माध्यम से गांव में विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा नागरिकों की समस्याओं पर जनभागीदारी के साथ चर्चा की जायेगी। खासकर घरकुल की प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र लाभार्थियों, महिलाओं और ग्रामीणों से अपने सुझाव एवं आपत्तियां ग्रामसभा में रखने की अपील की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने महिलाओं समेत सभी ग्रामीणों से 15 अगस्त की ग्रामसभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गांव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आहवान किया है।

रईस हाईस्कूल में जश्ने आजादी पर निबंध लेखन व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। जश्ने आजादी के अवसर पर रईस हाईस्कूल एंड जूनियर कॉलेज, भिवंडी में विद्यार्थियों की शैक्षणिक, रचनात्मक एवं बौद्धिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सुबह 8 बजे विद्यालय परिसर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल आमिर सिद्दीकी एवं असिस्टेंट हेडमास्टर मुखलिस मदू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत कर तिरंगे को सलामी दी तथा देश के प्रति प्रेम और निष्ठा का संकल्प व्यक्त किया। ध्वजारोहण के पश्चात विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना एवं रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सेकेंडरी स्कूल के 70 विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम जैसे विषयों को अपनी कलाकृतियों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं जूनियर कॉलेज के 60 विद्यार्थियों के बीच स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने अपने निबंधों में स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए देश के उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति की क्षमता और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया।

रियलमी ने 7000 एम.ए.एच की बैटरी और स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ रियलमी 16एक्स 5जी पेश किया, जिसका शुरूआती मूल्य 23,999 रुपये है

मुंबई। भारतीय युवाओं के सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड, रियलमी ने आज अपनी नंबर सीरीज में रियलमी 16एक्स 5जी का लॉन्च किया। यह अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर ऑल-राउंडर स्मार्टफोन है। रियलमी 16एक्स 5जी का डिजाईन आज के ऑलवेज-ऑन लाईफस्टाईल के अनुरूप है। इसलिए इस डिवाईस में 7000 एम.ए.एच की शक्तिशाली बैटरी, 45 वॉट की सुपरवूक फास्ट चार्जिंग, 144हट्र्ज का अल्ट्रा-ब्राईट डिस्प्ले, और 5 साल की स्मूथ परफॉर्मेंस दी गई है, जिससे आज के डायनामिक लाईफस्टाईल के लिए बेहतरीन पॉवर, एंटरटेनमेंट और लॉन्ग-टर्म रिलायबिलिटी मिलती है।

5 साल की स्मूथ परफॉर्मेंस, एडवांस्ड गेमिंग और 144 हट्र्ज का अल्ट्रा ब्राईट डिस्प्ले रियलमी 16एक्स 5जी को सालों तक स्मूथ परफॉर्मेंस प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह दैनिक उपयोग के लिए सबसे बेहतर स्मार्टफोंस में से एक है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5जी चिपसेट लगा है, जो 6एनएम प्रोसेस द्वारा बनाया गया है। यह 18 जीबी तक की डायनामिक रैम और 256 जीबी तक के स्टोरेज के साथ आता है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिव मल्टीटास्किंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक भरोसेमंद स्मार्टफोन है।

यह स्मार्टफोन एन्ड्रॉयड 16 पर आधारित रियलमी यू.आई 7.0 पर चलता है। इस डिवाईस में रियलमी का फ्लक्स इंजन और फ्लक्स एनिमेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देते हैं, ऐप लॉन्च की गति तेज कर देते हैं और एनिमेशन को फ्लुइड बनाकर रखते हैं, जिससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और ऐप्स के बीच स्विचिंग के दौरान ज्यादा स्मूथ एहसास मिलता है। लंबे समय तक भरोसा प्रदान करने के लिए रियलमी 16एक्स 5जी 5 साल की स्मूथ परफॉर्मेंस और एक्सटेंडेड यूज केयर और लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आता है। रियलमी 16एक्स 5जी को यूजेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए बनाया गया है। यह बहुत तेज, स्थिर और भरोसेमंद स्मार्टफोन है, जो आपको अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर स्मार्टफोन अनुभव प्रदान करता है।

गेम के शौकीनों के लिए रियलमी 16एक्स 5जी में जीटी बूस्ट और हाईपर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ 5300 मिमी2 का एयरफ्लो वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो रिसोर्सेज का इंटेलिजेंट एलोकेशन करते हुए फ्रेम रेट को स्टेब्लाईज करता है और लंबे गेमिंग सेशंस में हीट का इफेक्टिव मैनेजमेंट करता है। इसमें एक समर्पित वन-टैप कूलिंग फीचर भी दिया गया है, जो पीक परफॉर्मेंस के दौरान डिवाईस के तापमान को कम करता है, जिससे गेमिंग का स्थिर, आरामदायक और सबसे बेहतर अनुभव प्राप्त होता है।

एंटरटेनमेंट और गेमिंग का अनुभव बेहतर बनाने के लिए रियलमी 16एक्स 5जी में 6.8 इंच का विशाल अल्ट्रा-ब्राईट डिस्प्ले दिया गया है, जो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर व्यूइंग अनुभव प्रदान करता है। इसमें सेगमेंट का अग्रणी 144 हट्र्ज का रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स तक का हाई ब्राईटनेस मोड है, जिसकी मदद से यह डिस्प्ले रोजमर्रा की स्ट्रीमिंग, गेमिंग और आउटडोर ब्राउजिंग के दौरान अल्ट्रा-स्मूथ स्क्रॉलिंग, ज्यादा तेज टच रिस्पॉन्स और क्रिस्प एवं कम्फर्टेबल व्यूइंग अनुभव प्रदान करता है।

रियलमी 16एक्स 5जी में सेगमेंट की सबसे बेहतर 7000 एम.ए.एच की बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन पॉवर प्रदान करती है। इस बैटरी को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है। इसलिए छः सालों तक उपयोग करने के बाद भी इसकी 80 प्रतिशत हैल्थ बची रहती है। यह 1600 चार्जिंग सायकल्स तक को सपोर्ट करती है।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामी: शरद फागुराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित।RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

भाजपा की भव्य तिरंगा यात्रा में गूंजा राष्ट्रभक्ति का संदेश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति के नेतृत्व में गुरुवार को नगर पालिका टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट परिसर तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति के नारों और तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया।

तिरंगा यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर अटाला मस्जिद, ऐतिहासिक शाही किला, सद्भावना पुल और जोगियापुर होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। यहां शहीद स्तंभ तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर देश के वीर शहीदों को नमन किया गया। इसके बाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा केवल आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों और देशभक्ति के संकल्प का पर्व है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से अमर शहीदों को नमन करने के साथ देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया जा रहा है।

राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर देश और प्रदेश तिरंगामय

हो चुका है। तिरंगा यात्रा नई पीढ़ी को आजादी के महत्व और वीर सेनानियों के बलिदान से परिचित कराने का माध्यम है।

विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमें त्याग, शांति और समृद्धि की प्रेरणा देता है। विधायक रमेश सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा युवाओं में राष्ट्रसेवा और देश की अखंडता के प्रति समर्पण की भावना मजबूत करती है।

विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज किसी दल का नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के गौरव का प्रतीक है। पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि तिरंगे के सम्मान के लिए वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय ने आयोजन की सफलता पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया।

इस अवसर पर पूर्व विधायक बाकेलाल, नागेश्वर पांडेय, पंकज मिश्रा, राज पटेल, परविन्द चौहान, अमित श्रीवास्तव, विनय सिंह, अजय सरोज, नीरज मौर्य, पुष्पा निषाद, पीयूष गुप्ता, संदीप तिवारी, अजय सिंह, संतोष मिश्रा, राजकेशर पाल, धर्मेंद्र मिश्रा, डॉ. देवी प्रसाद सिंह, रीता जायसवाल, घनश्याम यादव, आमोद सिंह, डॉ. अमरनाथ पांडेय, रोहन सिंह, अमित पाठक, कुंवर दिग्विजय सिंह, सिद्धार्थ राय, अवनीश यादव, नरेंद्र उपाध्याय, अनिल गुप्ता, मेराज हैदर, राखी सिंह, प्रमोद प्रजापति, अतुल सिंह, शुभम मौर्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डिजिटल दौर में पत्रकारिता के लिए तकनीकी दक्षता जरूरी: बृजेश सिंह

मीडिया के बदलते दौर में मल्टी-स्किल पत्रकारिता जरूरी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में पत्रकारिता की बदलती चुनौतियों और मीडिया के बदलते स्वरूप पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। विभाग के पूर्व विद्यार्थी एवं इंडिया वॉइस चैनल के पूर्व प्रमुख, लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार बृजेश सिंह ने विद्यार्थियों को पत्रकारिता के बदलते दौर में तकनीकी दक्षता, लेखन, बोलने की कला और कैमरे के सामने प्रभावी प्रस्तुति के महत्व के बारे में जानकारी दी।

व्याख्यान में बृजेश सिंह ने कहा कि एक समय पत्रकारिता मुख्य रूप से अखबारों और फिर टेलीविजन तक सीमित थी। उस दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार नहीं था और प्रशिक्षण के अवसर भी सीमित थे। आज मीडिया का स्वरूप तेजी से बदल चुका है। डिजिटल मीडिया में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट तैयार करने वाले प्रतिभाशाली लोगों की मांग बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि आज के दौर में मीडिया संस्थानों को मल्टी-स्किल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। पहले जिस काम को करने के लिए चार लोगों की जरूरत होती थी, आज तकनीक के कारण कई काम एक ही व्यक्ति को करने पड़ रहे हैं। इसलिए पत्रकारिता के विद्यार्थियों को लेखन, बोलने, कैमरा फेसिंग, वीडियो निर्माण और डिजिटल कंटेंट तैयार करने सहित विभिन्न कौशलों में दक्ष होना चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों को लेखन की बारीकियां समझाते हुए कहा कि बोलना आसान है, लेकिन लिखना कठिन है। पत्रकारिता में अच्छे लेखन के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपने लिखे हुए कंटेंट को बार-बार पढ़ना चाहिए और उसमें आवश्यक सुधार एवं संपादन

बृजेश सिंह ने विद्यार्थियों को बताए लेखन और कैमरा फेसिंग के गुर

करना चाहिए। जितना अधिक व्यक्ति अपने लेखन और प्रस्तुति पर काम करेगा, पत्रकारिता की राह

उन्होंने सवाल पूछने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और कैमरे के सामने सहज रहने की तकनीक के बारे में भी

उतनी ही आसान होती जाएगी।

बृजेश सिंह ने जनसंचार विभाग के ऑडियो-विजुअल स्टूडियो में विद्यार्थियों को साक्षात्कार लेने की तकनीक तथा कैमरे को फेस करने के गुर भी बताए। उन्होंने व्यावहारिक रूप से समझाया कि इंटरव्यू लेते समय पत्रकार के भीतर आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है।

जानकारी दी।

जनसंचार विभाग के शिक्षक डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने प्रायोगिक तौर पर टेलीविजन इंटरव्यू की तकनीक समझाई। उन्होंने विद्यार्थियों को कैमरे के सामने सहज रहने, प्रभावी ढंग से सवाल पूछने और साक्षात्कार को स्वाभाविक संवाद में बदलने की तकनीक बताई।

उन्होंने कहा कि यदि किसी पत्रकार के पास बेहतर कंटेंट और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता है तो डिजिटल मीडिया में उसके लिए अवसर और पहचान दोनों हैं। विद्यार्थियों को बदलती तकनीक को चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए। पत्रकारिता के पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए नई तकनीकों को अपनाकर विद्यार्थी स्वयं को भविष्य के मीडिया के लिए तैयार कर सकते हैं।

कार्यक्रम में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ. मनोज मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार बृजेश सिंह का स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुनील कुमार ने किया तथा संचालन डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने किया। इस अवसर पर डॉ. चन्दन सिंह, डॉ. अमित मिश्र, आनंद सिंह, पंकज सिंह समेत विभाग के शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मां के दोनों हाथ ऐंठने के मामले में फिर गठित हुई तीन सदस्यीय जांच समिति

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। मंडलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में शासन ने एक बार फिर तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। यह कार्रवाई समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के बाद की गई है, जिसमें महिला के बेटे ने अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मां के दोनों हाथ ऐंठे जाने का आरोप लगाया था। मामले का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

डिप्टी सीएम के एक्शन के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक ने दिए पुनः जांच के निर्देश, तीन दिन में देनी होगी रिपोर्ट

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश डॉ. पवन कुमार अरुण की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, चिकित्सा अनुभाग-1 के निर्देश पर प्रकरण की पुनः जांच के लिए समिति गठित की गई है। जांच समिति में मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मंडल को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मंडल को सदस्य तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ डॉ. उमा शरण पांडेय को सदस्य नामित किया गया है।

महानिदेशक ने समिति को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर तीन दिन के भीतर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। दोबारा जांच समिति गठित होने के बाद जिला चिकित्सालय में मरीजों के साथ कथित व्यवहार, इलाज की व्यवस्था और लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की संभावना है।

जिला अस्पताल परिसर में राजनीतिक बैनर को लेकर उठे सवाल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय परिसर में समाज विकास क्रान्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह की ओर से

लगाया गया एक बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है। बैनर पर श्रावण मास, स्वतंत्रता दिवस एवं आगामी पर्वों की शुभकामनाएं दी गई हैं। हालांकि, सरकारी अस्पताल परिसर में राजनीतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति की ओर से बैनर लगाए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला चिकित्सालय जैसे सरकारी संस्थान किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के नहीं, बल्कि आम जनता के लिए संचालित होते हैं। ऐसे में परिसर में राजनीतिक दल या नेता से जुड़ी प्रचारात्मक सामग्री लगाए जाने से सरकारी संस्थान की निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अनुमति को लेकर भी उठे सवाल: लोगों का कहना है कि सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का बैनर या प्रचार सामग्री लगाने के लिए संबंधित विभाग अथवा सक्षम प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति आवश्यक हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि उक्त बैनर लगाने की अनुमति किस स्तर से दी गई और क्या इसे लगाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया।

चुनावी अवधि में भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों पर राजनीतिक प्रचार सामग्री को लेकर स्पष्ट प्रतिबंध लागू होते हैं। हालांकि, चुनावी आचार संहिता लागू न होने की स्थिति में भी सरकारी परिसर में बैनर लगाने की अनुमति संबंधित विभाग, स्थानीय प्रशासन तथा सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े नियमों के अधीन होती है।

प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग: बैनर को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन से मामले की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि बैनर लगाने की अनुमति नियमों के तहत दी गई है तो प्रशासन को इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, वहीं यदि बिना अनुमति बैनर लगाया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

फिलहाल जिला चिकित्सालय परिसर में लगे इस बैनर को लेकर राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकारी संस्थानों के इस्तेमाल और प्रशासनिक निष्पक्षता का सवाल चर्चा में है। अब देखना यह है कि अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं।

तिरंगे का सम्मान, राष्ट्र का अभिमान: प्रो प्रमोद यादव

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत

गुरुवार को देशभक्ति और स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर ने हर घर तिरंगा अभियान- 2026र के अंतर्गत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रतिरंगा एवं स्वच्छता अभियानर रहा, जिसका नारा था– ह्रतिरंगा सम्मान - स्वच्छ परिसरह्र।

स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ 13 अगस्त 2026 को प्रातः 9 बजे मुक्तांगन परिसर में हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। इस अवसर पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि ह्रतिरंगे का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र और जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्वच्छ परिसर और स्वच्छ पर्यावरण से ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है ह्र राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव ने कहा कि ह्रस्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि आज युवा पीढ़ी राष्ट्रहित और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति सजग है। यह अभियान तिरंगे के सम्मान और स्वच्छता के संकल्प को एक साथ जोड़ता है ह्र

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय, एनसीसी के प्रभारी ने कहा कि यह अभियान न केवल राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्वविद्यालय का संकल्प भी है।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के अधिकारियों एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स ने एक स्वर में आह्वान किया- आओ, तिरंगे का सम्मान करें और मिलकर बनाएं अपने परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर। शाम को सम्न्वयक द्वारा विभिन्न विभागों में हर घर तिरंगा अभियान एवं विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त परिसर एवं समाज अभियान के बारे में जागरूक किया गया।

रक्षाबंधन पर बहनों को योगी सरकार का तोहफा, यूपी में चलेंगी अतिरिक्त बसें

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार ने विशेष तैयारी की है। परिवहन विभाग ने 26 अगस्त से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसें चलाने और शत-प्रतिशत बसों को ऑनरोड रखने के निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की

बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर समेत प्रमुख रूटों पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए भी अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित रहेगा। त्योहार के दौरान परिवहन कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक रहेगी, ताकि बस संचालन प्रभावित न हो। कर्मचारियों को बेहतर सेवा के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रबंध किया गया है।

सरकार का उद्देश्य रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों को समय पर बस सेवा उपलब्ध कराना और भीड़ के बीच उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाना है।

आजमगढ़ में अनुज सिंह की शानदार उपलब्धि, NPCIL में वैज्ञानिक अधिकारी बने

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। सठियांव ब्लॉक के अतरडीहा गांव निवासी अनुज सिंह ने अपनी प्रतिभा, लगन और कड़ी मेहनत के दम पर प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयनित होकर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से परिवार सहित क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अनुज सिंह, पुत्र अशोक कुमार सिंह, ने बीटेक और एमटेक की शिक्षा पूरी करने के बाद देश की प्रतिष्ठित GATE परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने NPCIL की चयन प्रक्रिया में भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन करते हुए वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अपनी जगह बनाई। अनुज ने तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। निरंतर अध्ययन, अनुशासन और मेहनत

के बल पर उन्होंने GATE में सफलता हासिल की और इसके बाद NPCIL की चयन प्रक्रिया में भी सफलता का परचम लहराया। अनुज के चयन की जानकारी मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपनी सफलता का श्रेय अनुज ने माता-पिता, परिजनों और शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ अपनी मेहनत को दिया। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी NPCIL में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में चयनित होना उनके परिवार के साथ-साथ पूरे अतरडीहा और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।

पुलिस कार्यालय के पास युवती ने खाई सल्फास, मचा हड़कंप

जिला अस्पताल से गंभीर युवती बीएचयू रेफर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास बृहस्पतिवार को दोपहर करीब 12 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब न्याय की मांग लेकर पहुंची एक युवती ने कथित तौर पर सल्फास का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। युवती ने पुलिस और प्रशासन पर उचित न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही लाइन बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार, बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर निवासी 20 वर्षीय महिमा तिवारी पुत्री रमेश चंद्र तिवारी एक मामले में न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी। बताया जा रहा है कि युवती ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इसी दौरान उसने कथित तौर पर सल्फास का सेवन कर लिया। सल्फास खाने के बाद युवती की हालत बिगड़ने लगी। पुलिस ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी स्थित बीएचयू रेफर कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

शुरू हुई प्रदेशभर में दागी पुलिसकर्मियों की पहचान

गोरखपुर (उत्तरशक्ति)। गोरखपुर में बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश की पुलिस की छवि पर दाग लगा दिया है। दरिंदे सिपाही ने हवस का शिकार बनाकर मासूम की जान ले ली, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना न होने पाए, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने कवायद शुरू कर दी है। इस केस को आधार मानते हुए पुलिस मुख्यालय ने वर्दी की आड़ में अपराध करने वाले और संदिग्ध छवि वाले पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए अभियान शुरू किया है। हर जिले में ऐसे पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिनके खिलाफ आपराधिक केस, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अनुशासनहीनता या अन्य गंभीर आरोप दर्ज हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों में पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिका, विभागीय जांच, लंबित शिकायतों और दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा की जा रही है। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप या मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें चिह्नित कर वर्दी पर लगे दाग मिटाने को हर जिले में खंगाले जा रहे पुलिसकर्मियों के रिकॉर्ड गोरखपुर कांड के बाद संदिग्ध छवि वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें संवेदनशील जिम्मेदारियों से हटाने और विभागीय कार्रवाई तेज करने की भी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, उद्देश्य केवल लंबित मामलों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में किसी ऐसे पुलिसकर्मी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न मिले, जिसकी छवि संदिग्ध हो।

महिको के संस्थापक डॉ.बद्रीनारायण आर. बारवाले की जयंती पर विशेष आयोजन

महुली,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। महिको प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. बद्रीनारायण आर. बारवाले की जयंती के अवसर पर गुरुवार, 13 अगस्त को आदर्श इंटर कॉलेज, महुली दुद्धी, सोनभद्र में भव्य एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉ. बारवाले के जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों तथा कृषि एवं किसान हित में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया।

विद्यार्थियों को बांटी गईं कॉपियां और लड्डू, किसान हितों एवं आधुनिक कृषि के संदेश से रूबरू हुए छात्र-छात्राएं

कार्यक्रम में महिको प्राइवेट लिमिटेड के टेरिटरी मैनेजर रवि सिंह एवं किसान सलाहकार मिथिलेश मौर्य (दुद्धी) ने विद्यार्थियों को डॉ. बद्रीनारायण आर. बारवाले के जीवन परिचय और उनके द्वारा किसानों की उन्नति के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉ. बारवाले ने किसानों को उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक कृषि तकनीक तथा बेहतर कृषि व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस दौरान विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्र-छात्राओं को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों, उन्नत बीजों के महत्व और किसान प्रथम की विचारधारा के बारे में विस्तार से बताया गया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों से डॉ. बारवाले के जीवन से प्रेरणा लेकर मेहनत, नवाचार, अनुशासन और समाजहित की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

छात्र-छात्राओं में बांटी गई कॉपियां और लड्डू: जयंती समारोह को यादगार बनाने के लिए इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं को कॉपियां और लड्डू भी वितरित किए गए। उपहार पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यालय परिवार ने इसे शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़ा प्रेरणादायी आयोजन बताया।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से डॉ. बद्रीनारायण आर. बारवाले को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. बारवाले का जीवन हमें सिखाता है कि किसानों के हितों के प्रति समर्पण और कृषि क्षेत्र में दिए गए योगदान को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. राकेश कुमार कनौजिया, प्रवक्ता अमित कुमार मिश्रा, कृष्ण कुमार, जयप्रकाश शर्मा, आलोक कुमार, अभिषेक कुमार, अवधेश कुमार सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में उत्साह एवं प्रेरणादायी वातावरण बना रहा।

बाबा नगरी दूर है, जाना जरूर है... बोल बम के जयघोष से गूंजा जोरूखाड़

सुशील कुमार तिवारी

दुद्धी,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। सावन के पावन महीने में भोलेनाथ की भक्ति में डूबा जोरूखाड़ गांव गुरुवार को हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। दोपहर करीब एक बजे बैंड-बाजे के साथ लगभग 100 कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। कांवरिये नाचते-गाते और हाथों में भगवा ध्वज लिए ह्रबाबा नगरी दूर है, जाना जरूर है... बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा हैह्र के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बनाते रहे।

बैंड-बाजे के साथ 100 कांवरियों का जत्था बाबा धाम रवाना, ग्राम प्रधान विमल यादव ने झंडी दिखाकर किया रवाना

बाबा धाम रवाना होने से पूर्व कांवरियों का जत्था रेघड़ा स्थित शिव मंदिर पहुंचा। यहां श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का विधिवत दर्शन-पूजन किया और अपने क्षेत्र, परिवार तथा समाज की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया।

इसके बाद कांवरिये सुल्तानगंज पहुंचकर पवित्र गंगाजल उठाएंगे। वहां से पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके पश्चात बासुकिनाथ धाम में भी जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना करेंगे।

ग्राम प्रधान विमल यादव ने झंडी दिखाकर कांवरियों के जत्थे को रवाना किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। बैंड की धुन पर कांवरिये जमकर झूमे और ह्रबोल बम-बोल बमह्र के जयघोष से माहौल को भक्तिमय बना दिया।

जत्थे में विजय यादव, महेंद्र यादव, राधे यादव, रामधारी, विशुनधारी, बलराम यादव, राहुल यादव, विजयशंकर समेत करीब 100 कांवरिये शामिल रहे। इस अवसर पर राम कुमार यादव, प्रकाश यादव, उमेश यादव, राजेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने कांवरियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए बाबा भोलेनाथ से उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना की।

सुजानगंज को नगर पंचायत का दर्जा देने की उठी मांग

सुजानगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। स्थानीय क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को 13 अगस्त 2026 को एक पत्र भेजा गया जिसमें शासन स्तर से आवश्यक पहल और कार्यवाही की मांग की गयी है। पत्र में बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में सुजानगंज क्षेत्र में जनसंख्या, बाजार, व्यापारिक गतिविधियों और गैर-कृषि आधारित रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आस–पास के कई गांवों के लोग दैनिक रूप से सुजानगंज बाजार आते हैं जिससे इस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक महत्व लगातार बढ़ रहा है।

पत्र के अनुसार सुजानगंज अब पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़कर नगरीय स्वरूप ले चुका है। क्षेत्र के निरंतर विकास और बढ़ती आबादी के कारण सड़क, नाली, जल निकासी, स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था जैसी नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ गई है। पत्र में यह भी उल्लेख है कि सुजानगंज को नगर पंचायत का दर्जा

क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार को भेजा गया पत्र

मिलने से नागरिक सुविधाओं के विस्तार और रखरखाव को एक संस्थागत आधार मिलेगा। इससे विकास कार्यों की बेहतर योजना और क्रियान्वयन संभव होगा जिससे स्वच्छता, जल निकासी, सड़क, प्रकाश और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद है। स्थानीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

पत्र के माध्यम से शासन से अनुरोध किया गया कि सुजानगंज क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं और विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसे नगर पंचायत के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है। इस पत्र पर आनंदिता सिंह और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आलोक सिंह के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्रक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र सौंपते हुये क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, गैर-कृषि रोजगार, व्यापारिक गतिविधियों और राजस्व क्षमता का परीक्षण कर सुजानगंज को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने की संभावनाओं की जांच कराने की भी मांग किया। सुजानगंज को नगर पंचायत का दर्जा मिलने से क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ से की शुभेच्छा भेंट

-प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर(उत्तर शक्ति)। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का चार वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा क्रमांक 4 की विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ से शुभेच्छा भेंट की इस अवसर पर शहर के विकास, जनहित से विषयों एवं भविष्य के इंदौर के विकास के लिए विस्तृत जानकारी साझा किया। चार सालों में हुए कार्य का पूर्ण विवरण दिया। उन्होंने बताया कि विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ के मार्गदर्शन में संगठन निरंतर सशक्त होकर इंदौर की सेवा में नए आयाम स्थापित करता रहेगा, आशा है कि आप हम सब को सदा प्रेरणा देती रहे। महापौर ने कहा कि स्वच्छ, सुन्दर और नियमों का पालन करने वाला इंदौर ही हमारी पहचान है। महापौर ने जानकारी देते हुए कहा कि पेयजल और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 वर्ष पुरानी पाइप लाइनें बदली गई है। बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए नर्मदा परियोजना के चौथे चरण पर काम आगे बढ़ाया गया है। अपने चार सालों के कामकाज को अवगत कराया।

उत्तर यादव युवा संघ के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र जगरदेव यादव के पिताजी का निधन

कल्याण। उत्तर यादव युवा संघ (रजि.) के राष्ट्रीय सचिव एवं कल्याण जिला अध्यक्ष जितेंद्र जगरदेव यादव के पिताजी जगरदेव मगरू यादव (90 वर्ष) का गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को तड़के 1:30 बजे शायन अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से यादव समाज एवं परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत जगरदेव मगरू यादव का पार्थिव शरीर उनके निवास रूम नं. 5, न्यू शांति निवास, कमला निवास के पास, पूना लिंक रोड, काटेमानिवली, विठ्ठलवाड़ी, कल्याण पूर्व में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उनकी अंतिम यात्रा 13 अगस्त को सुबह 9 बजे निवास स्थान से निकाली गई। इसके बाद विठ्ठलवाड़ी पूर्व स्टेशन के पास स्थित हिंदू श्मशानभूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जगरदेव मगरू यादव के निधन पर उत्तर यादव युवा संघ (रजि.) ने गहरा शोक व्यक्त किया। संघ के पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। संघ ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें।

सेल्सफोर्स और त्रिपुरा सरकार ने 10,000+ लर्नर्स को स्किल प्रदान करने और डिजिटल वर्कफोर्स रेडीनेस बढ़ाने के लिए की पार्टनरशिप

मुंबई/बेंगलुरू। आज नंबर 1 एजेंटिक सी.आर.एम, सेल्सफोर्स और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (डी.आई.टी), त्रिपुरा सरकार के बीच साझेदारी की शुरूआत हुई है, जिसके अंतर्गत राज्य में डिजिटल स्किल्स की उपलब्धता और वर्कफोर्स रेडीनेस बढ़ाई जाएगी। इस सहयोग की घोषणा अगरतला में डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 में की गई। यह अभियान सेल्सफोर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रेलहेड के माध्यम से त्रिपुरा में बढ़े स्तर पर डिजिटल परिवर्तन लाने तथा स्टूडेंट्स, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर्स को ए.आई-संचालित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने में मदद करेगा। इस अभियान का उद्देश्य 2027 तक 10,000 से अधिक लर्नर्स को तैयार करना है। लोक सेवाओं, कार्यस्थलों और व्यवसायों में ए.आई की भूमिका बढ़ रही है, इसलिए यह पार्टनरशिप लर्नर्स को ऐसी प्रैक्टिकल डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्किल्स प्रदान करने के लिए की गई है, जो धीरे-धीरे काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही हैं। यह कोर्स बिगनर्स और इंटरमीडिएट लर्नर्स को अपनी गति से सीखने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। यह लर्नर्स को सी.आर.एम, बिजनेस एनालिसिस, टेक्नोलॉजी फंडामेंटल आदि के लिए गाईडेड लर्निंग प्रदान करता है। सेल्सफोर्स लर्नर्स को इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने और लर्निंग के पूरे सफर में सहयोग प्रदान करने के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन रिसोर्स भी उपलब्ध कराएगा। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और स्किल डेवलपमेंट एजेंसियों से प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें नियुक्त करेगा तथा राज्य में इस प्रोग्राम की उपलब्धता व जागरूकता बढ़ाएगा।

किरन गिट्टे, आई.ए.एस, सेक्रेटरी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, त्रिपुरा सरकार ने कहा, सेल्सफोर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप त्रिपुरा के डिजिटलाईजेशन के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पॉलिसी की मजबूत बुनियाद के साथ यह पार्टनरशिप हमारे स्टूडेंट्स, सरकारी कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर्स को भविष्य की डिजिटल स्किल प्रदान करेगी तथा इनोवेशन और समावेशी विकास लेकर आएगी।

हम एक आत्मनिर्भर आई.टी ईकोसिस्टम बनाने और त्रिपुरा के कर्मचारियों को अपनी पूरी क्षमता के विकास में मदद करने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर, सेल्सफोर्स के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। जेया सुलु गेशन बी, आई.ए.एस, डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, त्रिपुरा सरकार ने कहा, त्रिपुरा में हर साल बड़ी संख्या में टेलेंट का विकास हो रहा है। हम इस टेलेंट को विश्व के लिए जरूरी स्किल्स प्रदान करना चाहते हैं। सेल्सफोर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप हमें टी.आई.डी.ई.जैड, आई.टी पार्क और ए.आई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में अपने निवेश को मजबूती देने में मदद करेगी।

भाजपा ने शिवाजी तालाब परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान

दुद्धी ,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 9 अगस्त 2026 से चल रहे स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुद्धी नगर पंचायत स्थित शिवाजी तालाब परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया।

अभियान में भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता और नगर पंचायत चेयरमैन कमलेश मोहन ने भी सहभागिता की। इस दौरान कार्यकताओं ने तालाब परिसर की साफ-सफाई की और लोगों से सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने की अपील की। भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता एवं चेयरमैन कमलेश मोहन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जिले के विभिन्न हिस्सों में शहीद स्मारकों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 'हर घर तिरंगा' और स्वतंत्रता सप्ताह का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

मंडल अध्यक्ष दीपक शाह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करने के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने और स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की।

इस अवसर पर जिलामंत्री मनोज सिंह बबलू, पूर्व जिलामंत्री दिलीप पांडेय, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुमित सोनी, पूर्व मंडल महामंत्री मनीष जायसवाल, उपेन्द्र एडवोकेट जितेंद्र चंद्रवंशी, मंडल महामंत्री प्रेम नारायण मोनू, अंशुमान रॉय, मंडल उपाध्यक्ष पंकज अग्रहरि, हिमांशु चौरसिया, गोरखनाथ अग्रहरि, बुल्लू, युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय चंद्रवंशी, धर्मेंद्र पाल, विकास सोनी, मोहित अग्रहरि, आयुष केशरी, धीरज जायसवाल, अंका कुमार, दिग्गज जौहरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भिवंडी-वाड़ा रोड और वडोदरा-मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे के बीच रैंप को जल्द मंजूरी देने की मांग

पालघर। पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सावरा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर भिवंडी-वाड़ा रोड (SH-35) को वडोदरा-मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण कनेक्टिंग रोड और एंट्री-एग्जिट रैंप के रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट को तत्काल प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी देने की मांग की।

डॉ. सावरा ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना के तहत भिवंडी-वाड़ा रोड (SH-35) और वडोदरा-मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 31+313 के बीच तथा किलोमीटर 31+490 से 32+700 तक सुपेगांव-लामाज क्षेत्र को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है। यह परियोजना भारतमाला परियोजना फेज-वन के अंतर्गत निर्माणाधीन आठ-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड वडोदरा-मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे के अकलोली-अमाने सेक्शन, पैकेज-8 का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कनेक्टिविटी में होगा बड़ा सुधार

प्रस्तावित रैंप और लिंक रोड के निर्माण से भिवंडी-वाड़ा रोड और वडोदरा-मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे के बीच सीधी और सुगम कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इससे वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों पर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे यात्रा समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी और सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा। इस परियोजना का लाभ किसानों, स्थानीय नागरिकों, उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी मिलेगा। कृषि उपज, औद्योगिक माल और यात्रियों के परिवहन में तेजी आने से भिवंडी, सुपेगांव, लामाज, अंबाडी तथा आसपास के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को

डॉ. हेमंत सावरा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलने की उम्मीद है।

रिवाइज्ड कॉस्ट की मंजूरी का इंतजार

डॉ. सावरा के अनुसार, परियोजना का रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट फिलहाल अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा में है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर रिवाइज्ड लागत को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया, ताकि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जा सके।

डॉ. सावरा ने कहा कि यह परियोजना केवल सड़क संपर्क को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पालघर जिले और आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक, ग्रामीण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। एक्सप्रेसवे नेटवर्क तक बेहतर पहुंच मिलने से क्षेत्र में निवेश, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है।

1300 एकड़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंटर की मांग, 3 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य

वसई-विरार। शहर के सुनियोजित विकास और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1300 एकड़ सरकारी जमीन पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंटर बनाने की मांग भाजपा विधायक राजन नाइक ने पालकमंत्री एवं राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक के सामने रखी है। बुधवार को मंत्रालय में वसई-विरार सब-रीजन के विकास प्रस्तावों और बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठाया गया।

राजन नाइक ने कहा कि वसई रोड और नालासोपारा रेलवे स्टेशन के आसपास उपलब्ध करीब 1300 एकड़ जमीन को MMRDA को हस्तांतरित कर BKC की तर्ज पर आधुनिक आर्थिक केंद्र विकसित किया जाना चाहिए। इससे वसई-विरार में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे और मुंबई, ठाणे व बोईसर पर रोजगार के लिए निर्भरता कम होगी।

प्रस्तावित केंद्र में IT बिजनेस पार्क, ग्रीन डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया गया है। विधायक के अनुसार, इससे करीब 3 से 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है और क्षेत्र में 25 से 40 हजार करोड़ रुपये तक का निजी निवेश आने की संभावना है। बाढ़ नियंत्रण को भी प्राथमिकता राजन नाइक ने 1300 एकड़ जमीन में से कम से कम 15 प्रतिशत यानी करीब 195 एकड़ क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के लिए रखने तथा होल्डिंग तालाब बनाने की मांग की। उन्होंने शहर के नालों को चौड़ा करने और मानसून के दौरान पानी की निकासी तेज करने के लिए वसई खाड़ी में जमा गाद की ड्रेजिंग कराने का भी सुझाव दिया।

उन्होंने MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिशनर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित कर विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने की मांग की। प्रस्ताव में 80 से 85 प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक विकास और शेष 15 से 20 प्रतिशत नागरिक सुविधाओं व बाढ़ नियंत्रण के लिए रखने का सुझाव है। राजन नाइक ने बताया कि 30 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष भी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंटर की मांग रखी गई थी। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद MMRDA ने वसई-विरार में डेवलपमेंट सेंटर के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना वसई-विरार को भविष्य में रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा केंद्र बना सकती है।

श्रीमद्भगवद्गीता ग्रंथ का गरिमामय विमोचन

मुंबई। आदिवासी जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित मानवसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना के गौरवपूर्ण 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बिड़ला मातुश्री सभागार मुंबई में आयोजित एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातनश्री पंडित प्रदीप व्यास जी महाराज द्वारा विवेचनात्मक, सरल एवं भावार्थपूर्ण शैली में रचित श्रीमद्भगवद्गीता ग्रंथ का विधिवत विमोचन मारवाड़ी समाज के प्रतिष्ठित पुरोधाओं एवं भामाशाहों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।

पंडित व्यास जी महाराज इससे पूर्व अत्यंत सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण हिंदी भाषा में श्रीरामचरितमानस, श्रीमद्भागवत महापुराण, रामायण तथा हृदयस्पर्शी श्री कृष्ण कथामृत का भावार्थपूर्ण लेखन कर अपनी विशिष्ट साहित्यिक पहचान स्थापित कर चुके हैं।

उनकी रचनाओं में धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों को सहज भाषा में जन-जन तक पहुंचाने का विशेष प्रयास दिखाई देता है। मानवसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपनी दो दशक लंबी सेवा-यात्रा में निराश्रित एवं जरूरतमंद कैंसर पीड़ितों को लंबे समय तक सहायता उपलब्ध कराने का पुनीत कार्य किया है। वर्तमान में ट्रस्ट द्वारा मानवसेवा धर्मार्थ आवासीय आदिवासी विद्यालय तथा श्री सियाराम मंदिर (निर्माणाधीन) जैसे महत्वपूर्ण एवं सेवा-समर्पित प्रकल्पों को भी पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्रीमद्भगवद्गीता ग्रंथ के विमोचन समारोह में समाज के अनेक प्रतिष्ठित मारवाड़ी समाजसेवियों, भामाशाहों एवं सेवा-शिरोमणियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इनमें प्रमुख रूप से अमरीश अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, धर्मप्रवर्तक सूरज प्रकाश बागला, दिनेश कनोडिया, अनूप गनेरीवाल, इंद्र कुमार पुगलिया, सत्यनारायण अग्रवाल, ब्रजेंद्र कागजी, सियाराम ग्रुप के रमेश पोद्दार, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, राजेंद्र घुवालेवाला, रामेश्वर लाल काबरा, महेश अग्रवाल, शेयर मार्केट के अग्रज शिरोमणि राकेश कठोतिया, राम प्रकाश बूबना, आलोक अग्रवाल एवं मधुसूदन माहेश्वरी, हास्य सम्राट सुरेश मिश्र सहित अनेक गणमान्य समाजसेवी उपस्थित रहे।

पानी के बढ़े बिल और गड्ढों को लेकर भाजपा का महानगरपालिका के खिलाफ मोर्चा

वसई-विरार। पानी के बिल में बढ़ोतरी, घरों के किराए में वृद्धि, सड़कों पर गड्ढे, कुत्तों की नसबंदी में कथित घोटाला और बिना अनुमति निर्माण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने वसई-विरार महानगरपालिका प्रशासन और सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

गुरुवार को नालासोपारा पश्चिम स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के नेता मनोज गोपाल पाटिल, जिला अध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल, ग्रुप लीडर अशोक शेळके और मनोज बारोट ने महानगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

मनोज पाटिल ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के वित्तीय वर्ष में अधिकृत नल कनेक्शनधारकों के पानी के बिल

पिछले वर्ष की तुलना में करीब 100 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। साथ ही जल आपूर्ति लाभ कर और सीवेज सुविधा लाभ कर के कारण नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। भाजपा का आरोप है कि इन फैसलों से मकानों के किराए में भी करीब 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि नागरिक पूरे महीने का पानी का बिल भरने के बावजूद कई इलाकों में नियमित पानी नहीं मिल रहा है। कम दबाव, पाइपलाइन की खराबी और बिजली कटौती के कारण लोगों को टैंकरों पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पार्टी ने जल आपूर्ति विभाग से अनधिकृत पानी के इस्तेमाल और लंबित बिलों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।

सड़कों की बदहाली पर भी सवाल

शहर की कई खराब सड़कों को लेकर भाजपा ने सत्ताधारी बीवीए पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए जिन नेताओं ने गड्ढों को लेकर आंदोलन किए थे, वे सत्ता में आने के बाद चुप हैं। अमृत योजना 2.0 और नालासोपारा जोन-3 सीवेज परियोजना के चलते जगह-जगह हुई खुदाई से नागरिकों की परेशानी और बढ़ गई है।

भाजपा ने सड़क मरम्मत के बजट में कथित अतिरिक्त खर्च पर भी सवाल उठाते हुए 44.92 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च और सड़क निर्माण की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की है।

16 अगस्त को निकलेगा मोर्चा

भाजपा ने घोषणा की कि इन सभी मुद्दों को लेकर रविवार, 16 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजे जकात नाका, विरार पश्चिम से महानगरपालिका मुख्यालय तक मोर्चा निकाला जाएगा। पार्टी ने नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि नागरिकों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना उन पर अतिरिक्त करों का बोझ डालना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

फोनपे ने प्रमुख बैंक और NBFC के साथ मिलकर लॉन्च किया फिक्स्ड डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन

मुंबई। फोनपे ने आज टॉप बैंकों और NBFC के साथ साझेदारी करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर फिक्स्ड डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन की आधिकारिक शुरूआत की घोषणा की। अपनी फाइनेंशियल सर्विस के दायरे को बढ़ाते हुए, फोनपे ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में एक नया और अपनी तरह का पहला डिजिटल माइक्रो-सेविंग्स प्रॉडक्ट – डेली रिकरिंग डिपॉजिट भी पेश किया है। इस सुविधा में शुरूआती निवेश रोजाना मात्र 100 है। इस तरह यूजर्स, कम निवेश में ही बचत करने की अच्छी आदत डाल सकते हैं। इस लॉन्च के जरिए यूजर्स सीधे फोनपे ऐप में ही FD खोल सकते हैं, जिसे बचत का एक सुरक्षित और कम जोखिम वाला विकल्प माना जाता है। यहाँ यूजर्स भरोसेमंद पार्टनर बैंकों से FD आसानी से खोज सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं, और तुरंत बुक कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, पार्टनर बैंकों में आपकी FD पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख तक की राशि का इंश्योरेंस मिलता है।

इसके अलावा, इस सुविधा से यूजर्स को कई बैंकों में निवेश करने का मौका मिलता है और वे फोनपे ऐप से ही अपनी सभी FD को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस घोषणा की सबसे बड़ी बात "डेली फ्ल(SIP)" की लॉन्चिंग है, जिसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पेश किया गया है। डेली RD एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे बैंक डिपॉजिट जैसी सुरक्षा और भरोसे के साथ-साथ डेली SIP के सुविधाजनक और ऑटोमेटेड सिस्टम को साथ मिलाकर तैयार किया गया है। इसके जरिए आम उपभोक्ता, मिलेनियल्स, जेन-जी, और ऐसे लोग बड़ी आसानी से हर दिन 100 से लेकर 1,000 तक की छोटी राशि को ऑटोमैटिक रूप से निवेश के लिए सेट कर सकते हैं जिन तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच कम है। UPI ऑटोपे की आसान और इसके बड़े नेटवर्क के साथ, बचत का यह माइक्रो-सेविंग सिस्टम तुरंत पैसे निकालने की शानदार सुविधा भी देता है। इस लॉन्च के बारे में बात करते हुए, फोनपे के वीपी और हेड ऑफ पेमेंट्स, दीप अग्रवाल ने कहा, फोनपे में हमारा लक्ष्य वित्तीय सेवाओं तक हर भारतीय की पहुँच को आसान बनाकर उनके आर्थिक विकास को रफ़्तार देना है। फिक्स्ड डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन और डेली RD प्रॉडक्ट की लॉन्चिंग इस दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है।

बजाज जनरल इंश्योरेंस ने रक्षा कर्मियों के लिए प्रोशील्ड व नया और बेहतर वीपे 2.0 लॉन्च किया

पुणे/मुंबई। भारत की प्रमुख प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व नाम बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने आज रक्षा कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोटर इंश्योरेंस समाधान प्रोशील्ड और आज के कनेक्टेड वाहनों और बदलते मोबिलिटी जोखिमों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए अपने अगली पीढ़ी के मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट वी-पे 2.0 को लॉन्च करने की घोषणा की। हमारे रक्षा कर्मी देश की सीमाओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनकी नौकरी की वजह से उन्हें अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग, ड्यूटी से जुड़ी ज़िम्मेदारियों और लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनके समर्पण और सेवा को ध्यान में रखते हुए प्रोशील्ड को खास तौर पर तैयार किया गया है। यह सैन्य जीवन से जुड़ी खास चुनौतियों को ध्यान में रखकर सुरक्षा, सुविधा और भरोसेमंद आर्थिक सहायता प्रदान करता है, फिर चाहे ड्यूटी के लिए उन्हें देश के किसी भी कोने में जाना पड़े। वाहन रिलोकेशन प्रोटेक्शन, जिसमें एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग के बीच लाइसेंस प्राप्त कैरियर से वाहन ले जाने के दौरान पॉलिसी की अवधि बढ़ाने की सुविधा और कैरियर से वाहन ले जाते समय हुई ऐसी पात्र दुर्घटनाओं में नो क्लेम बोनस की सुरक्षा शामिल है, जिनमें बीमित व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती।

ट्रैवल इमरजेंसी प्रोटेक्शन जिसमें एयरपोर्ट जाते समय वाहन दुर्घटना के कारण फ्लाइट छूटने या होटल में रुकने पर हुए खर्च की पॉलिसी की शर्तों के अनुसार भरपाई की जाती है।

डॉक्यूमेंट लॉस प्रोटेक्शन, जिसमें बीमित व्यक्ति और उसके जीवनसाथी के वाहन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, खो जाने पर उन्हें दोबारा बनवाने के लिए फाइनेंशियल सहायता दी जाती है। प्राथमिकता के आधार पर खास सहायता, आपकी जरूरत के अनुसार क्लेम में मदद और देशभर में 7,300 से ज्यादा गैरेज के नेटवर्क की सुविधा। इन-बिल्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के तहत जीरो डेप्रिसिएशन (अनलिमिटेड क्लेम के साथ), डिडक्टिबल में छूट, रोडसाइड असिस्टेंस, टायर कवर, रिम कवर, चूहे से होने वाले नुकसान का कवर, टोइंग कवर, भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, रैली कवर और एक्सेसरीज कवर शामिल हैं।

जैसे-जैसे वाहन ज्यादा कनेक्टेड, सॉफ्टवेयर पर आधारित और तकनीकी रूप से एडवांस होते जा रहे हैं, ग्राहक भी चाहते हैं कि मोटर इंश्योरेंस सिर्फ सामान्य दुर्घटना से होने वाले नुकसान की सुरक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि उनकी बदलती जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़े। वीपे की सफलता के बाद, वीपे 2.0 को अब एक ऐसे ऑल-इन-वन मोटर इंश्योरेंस समाधान के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है, जिसमें एक ही पॉलिसी के तहत कई तरह के कवर शामिल हैं। इससे ग्राहकों को अलग-अलग ऐड-ऑन कवर चुनने की जरूरत कम हो जाती है।

बोइसर में 30 अगस्त को होगा बेटी के सम्मान में आईपीसी मैदान में का दूसरा मासिक कार्यक्रम

बोइसर/पालघर। अकेली माताओं की निराश्रित बेटियों के सहयोग, सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से बेटी के सम्मान में आईपीसी मैदान में अभियान के अंतर्गत दूसरा मासिक कार्यक्रम आगामी 30 अगस्त 2026, रविवार को बोइसर के भीम नगर स्थित त्रिगुण विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा।

कार्यक्रम का आयोजन आईपीसी एवं अनुश्री फाउंडेशन के सौजन्य से किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन बच्चियों तक सहायता पहुंचाना है, जिनकी माताएं अकेले परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। संस्था की ओर से ऐसी बच्चियों की शिक्षा, आवश्यक सामग्री एवं अन्य जरूरतों में यथासंभव सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। श्रीमती पुष्पा तिवारी को सम्मान मूर्ति के रूप में सम्मानित किया जाएगा। वहीं श्री मनोज मिश्र एवं एडवोकेट रविंद्र मिश्र विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं अन्य अतिथियों के नामों की घोषणा आयोजकों द्वारा बाद में की जाएगी।

कार्यक्रम के आयोजकों में डॉ. परमिंदर पाण्डेय, श्री उमाशंकर सिंह, श्री बृजेश पाण्डेय एवं श्रीमती रानी गुप्ता शामिल हैं। आयोजकों ने सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों से कार्यक्रम में अपनी सहभागिता और सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

कार्यक्रम को सफल बनाने में विभिन्न सहयोगियों का भी योगदान रहेगा। कार्यक्रम स्थल के लिए श्रीमती पुष्पा तिवारी, पानी की व्यवस्था के लिए श्री मनोज मिश्र, साहित्य सामग्री के लिए श्री विष्णेश त्रिपाठी तथा रामनामी के लिए श्री बृजेश पाण्डेय ने सहयोग प्रदान करने की सहमति दी है। इसके अलावा नाश्ता, बैनर, ट्रॉफी, शॉल, श्रीफल, तुलसी पत्र आदि व्यवस्थाओं के लिए भी सहयोग जुटाया जा रहा है।

आयोजकों ने कहा कि समाज में बेटियों के सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद बच्चियों को सहयोग देने के साथ-साथ समाज के सक्षम लोगों को भी इस सामाजिक पहल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

खुद को बताती थी वकील, नईबस्ती में कथित अनैतिक व्यापार के अड्डे पर छापा, संचालिका ममता सिंह फरार

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र के नईबस्ती में कथित अनैतिक व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। एनजीओ से मिली सूचना के सत्यापन के बाद एसीपी कैंट अपूर्व पाण्डेय के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने कार्रवाई की। मौके से दो युवतियों और दो ग्राहकों को पकड़ा गया, जिनमें एक युवती के नाबालिग होने की बात सामने आई है। पुलिस ने आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होने का भी दावा किया है। कार्रवाई के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस मकान संचालक, मकान मालिक और युवतियों के वहां पहुंचने के माध्यम की जांच कर रही है। स्थानीय स्तर पर मकान मालिक के खुद को अधिवक्ता बताने की चर्चा है, जिसकी पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नाबालिग के सामने आने से मामले की गंभीरता बढ़ गई है और पुलिस संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है।

Chheda Specialities Food के पालघर प्लांट के लाइसेंस से निलंबन 48 घंटे में हटाया गया

Chheda's
SINCE 1993

पालघर। छेड़ा स्पेशियलिटीज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज पुष्टि की कि FSSAI ने महाराष्ट्र स्थित उसके पालघर प्लांट के लाइसेंस से निलंबन 48 घंटे में हटाया गया। कंपनी ने निरीक्षण के दौरान उठाए गए सभी बिंदुओं पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कदम पूरे किए और विभाग को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। निलंबन हटाए जाने के बाद प्लांट का लाइसेंस अब पूरी तरह प्रभावी है और संचालन सामान्य रूप से जारी रह सकता है। Chheda Specialities Foods इस निर्णय का स्वागत करती है और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता एवं अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, छेड़ा स्पेशियलिटीज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा: हम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा दिखाई गई तत्परता और सहयोग की सराहना करते हैं तथा अपने पालघर संयंत्र के लाइसेंस की बहाली का स्वागत करते हैं। लाइसेंस की त्वरित बहाली कंपनी द्वारा समय पर की गई कार्रवाई और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता एवं अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने उपभोक्ताओं को उसी देखभाल और निरंतरता के साथ सेवा प्रदान करते रहने के लिए तत्पर हैं, जो तीन दशकों से भी अधिक समय से Chheda Specialities Foods की पहचान रही है। पालघर संयंत्र में अब पुनः परिचालन शुरू कर दिया गया है, जिससे Chheda Specialities Foods अपने उपभोक्ताओं, रिटेल भागीदारों और वितरकों को उसी निरंतरता, स्थिरता और देखभाल के साथ सेवा देना जारी रख सकेगी, जो तीन दशकों से अधिक समय से कंपनी की पहचान रही है। पालघर में परिचालन कुछ समय के लिए रोका गया था, जबकि डीहैं के अन्य सभी संयंत्र पूरी तरह से परिचालन में रहे और उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कंपनी अपने सभी परिचालनों में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता एवं अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

तिरंगे के साथ चलती रही काशी, जैसे सड़क पर उतर आया हो पूरा भारत

-सुरेश गांधी

वाराणसी। स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुवार को काशी की सड़कों पर ऐसा दृश्य दिखा, मानो पूरा शहर तिरंगे के साथ चल पड़ा हो। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से निकली ढ़ाहर घर तिरंगा यात्राढ़ मलदहिया और लहुराबीर होते हुए डॉ. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक पहुंची तो यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभावना का उत्सव बन गई। हजारों लोगों की मौजूदगी, देशभक्ति गीतों की गूंज और तिरंगे के प्रति उमड़ते जज्बे ने पूरे मार्ग को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया।

यात्रा शुरू होने से पहले ही विद्यापीठ परिसर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्कूली बच्चे कतारों में तिरंगा थामे खड़े थे, युवा समूहों में नारे लगा रहे थे और महिलाएं बच्चों के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर तस्वीरें खिंचवा रही थीं। पीएसी और पुलिस बैंड की देशभक्ति धुनें बजते ही वातावरण ढ़ाभारत माता की जयढ़ और ढ़ावंदे मातरमढ़ के नारों से गूंज उठा।

सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र वह लंबा तिरंगा रहा, जिसे दर्जनों युवाओं ने दोनों हाथों से थाम रखा था। सड़क पर दूर तक फैला तिरंगा देखने के लिए लोग रुकते, उसे छूकर माथे से लगाते और उसके साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। यात्रा के लगभग हर मोड़ पर लोग मोबाइल से वीडियो बनाते और तस्वीरें खींचते नजर आए।

झांकियों ने यात्रा को विशेष रूप दिया। सबसे आगे चल रहे रथ पर बालिकाएं भारत माता और राष्ट्रनायिकाओं की वेशभूषा में सजी थीं। उनके हाथों में तिरंगे थे और चेहरे पर गंभीर भाव। भीड़ उन्हें

देखकर हाथ जोड़ रही थी। कई लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है, जैसे सचमुच मां भारती यात्रा में साथ चल रही हों।

दूसरे रथ पर फूलों से सजा भारत का विशाल नक्शा था, जबकि तीसरे रथ पर नए संसद भवन की प्रतिकृति बनाई गई थी। इन दोनों झांकियों के सामने लोग रुक-रुककर तस्वीरें लेते रहे। बच्चे अपने अभिभावकों से भारत के नक्शे के बारे में पूछते दिखाई दिए।

यात्रा जब मलदहिया चौराहे पर पहुंची तो जनप्रतिनिधियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद लहुराबीर चौराहे पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान ढ़ाशहीदों अमर रहोढ़ के नारे गूंजते रहे और वातावरण भावुक हो उठा।

मार्ग में जगह-जगह स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कई व्यापारियों ने पानी और मिठाई की व्यवस्था की। देशभक्ति गीतों की धुन पर बच्चे कदम मिलाते रहे और युवा समूहों में तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ते रहे। प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि तिरंगा भारत की पहचान, स्वाभिमान और शक्ति का प्रतीक है तथा युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया।

डॉ. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में यात्रा के समापन पर राष्ट्रगान हुआ। हजारों लोग सावधान मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते रहे और पूरा परिसर तिरंगे के सम्मान में एक स्वर हो गया।

यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, महापौर अशोक कुमार तिवारी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. नीलकंठ तिवारी, डॉ. अवधेश सिंह, सुनील कुमार पटेल, टी. राम, क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, जिला अध्यक्ष रामसकल पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक शामिल रहे।

काशी की सड़कों पर लहराते हजारों तिरंगों और गूंजते देशभक्ति नारों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर के माहौल को पूरी तरह राष्ट्रप्रेम से सराबोर कर दिया।

युवा पीढ़ी भारत में घर के मालिक बनने की आकांक्षाओं को दे रही है बढ़ावा

मुंबई। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, मैजिकब्रिक्स के नवीनतम हाउसिंग सेंटीमेंट इंडेक्स में युवा भारतीयों के बीच घर के मालिक बनने की मजबूत आकांक्षाएं सामने आई हैं। सभी आयु वर्गों में Gen Z ने सबसे उच्च हाउसिंग सेंटीमेंट दर्ज किया है। पहली बार घर खरीदने वालों ने 130 के उच्चतम HSI के साथ सभी खरीदार वर्गों में बढ़त दर्ज की। इसके बाद घर खरीदने की इच्छा रखने वाले किरायेदारों का HSI 118 और दूसरा घर खरीदने की योजना बना रहे मौजूदा गृहस्वामियों का HSI 110 रहा। पहली बार घर खरीदने वालों में लगभग 75% की आयु 44 वर्ष तक है, जो भारत में घर के स्वामित्व की मांग में युवा परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। निष्कर्षों से आवास संबंधी निर्णय लेने वालों के व्यापक आधार का भी संकेत मिलता है। HSI सर्वेक्षण में महिलाओं की भागीदारी पिछले संस्करण में 18% से बढ़कर अगस्त 2026 में 40% हो गई, जो पिछले संस्करण की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। घर खरीदने की आकांक्षाएं मजबूत बनी हुई हैं, हालांकि खरीदार अब अपनी अपेक्षाओं को लेकर अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं। वर्तमान में भारतीय होमबायर्स ऐसी संपत्तियों को लक्ष्य बना रहे हैं, जिनका औसत मूल्य उनकी वार्षिक घरेलू आय का 4.9 गुना है, जबकि पिछले संस्करण में यह 5.2 गुना था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 69% उत्तरदाताओं को अगले एक वर्ष में या तो कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होने या अधिकतम 5% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह निकट अवधि में संपत्ति की कीमतों में वृद्धि को लेकर अधिक संतुलित और सतर्क अपेक्षाओं को दर्शाता है। युवा खरीदार बड़े घरों की प्राथमिकता को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

'आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट हर' देगा भारतीय महिलाओं को उनकी आर्थिक यात्रा के हर चरण में सहयोग

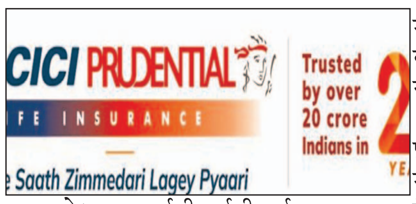

ठाणे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट हर लॉन्च किया है। यह खासतौर पर महिलाओं के लिए तैयार किया गया एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म प्लान है। इस प्लान को लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ और वेलनेस फायदों को जोड़कर महिलाओं की बदलती सुरक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट हर महिलाओं के जीवन के अहम पड़ावों पर उन्हें मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए कई खास सुविधाएं देता है। इसमें 15% लाइफटाइम प्रीमियम डिस्काउंट, महिला-विशेष हेल्थ मैनेजमेंट और वेलनेस सेवाएं, और प्रेग्नेंसी ब्रेक फीचर जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे महिलाएं प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी प्रीमियम किश्तों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं। इसके अलावा ये प्लान चाइल्ड एजुकेशन केयर भी देता है, जिसमें 10 साल तक हर साल बढ़कर मिलने वाली इनकम का लाभ मिलता है। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को मिलने वाला डेथ बेनिफिट अगले 10 सालों तक हर साल 10% बढ़कर नियमित आय के रूप में मिलता है। इस लॉन्च के बारे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, विकास गुप्ता ने कहा, ‘‘भारतीय महिलाएं कई भूमिकाएं निभाती हैं। इस वजह से उनकी वित्तीय योजना की जरूरतें अलग होती हैं और जीवन के अलग-अलग चरणों में बदलती रहती हैं। आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट हर को व्यापक सुरक्षा देने के साथ ही उनकी अनोखी स्वास्थ्य और वेलनेस जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ प्रेग्नेंसी ब्रेक और लाइफटाइम डिस्काउंट जैसी सुविधाओं को जोड़कर, हम एक ऐसा समाधान दे रहे हैं जो महिलाओं को उनके वित्तीय भविष्य और सेहत दोनों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा मिशन न्यू इंडिया के माध्यम से भारत के सभी राज्यों से आए हुए प्रविधियों का आयोजन संपन्न

विशाखापट्टनम (उत्तर शक्ति)। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा मिशन न्यू इंडिया के माध्यम से विशाखापट्टनम में विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। विशेष अधिवेशन में उपस्थित सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही तथा विधार्थी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने सभी राज्यों के विद्यार्थियों के शिक्षा की गुणवत्ता एवं उनकी समस्याओं को दूर करने का आह्वान लिया और उन्हें विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का निर्देश भी दिया गया राज्य में शिक्षा क्षेत्र में सभी राज्य भाषा के विषय अनिवार्य हो जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान हो सके एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ विद्यार्थियों को एक समान फीस का लाभ मिले एवं रोजगार भी उपलब्ध हो सके इसके लिये प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि विद्यार्थियों को आने वाले कठिनाइयों से अवगत करवाया जा सके।

मुंबई की सबसे बड़ी हार्ड-रॉक टीबीएम ‘अर्जुन’ काम पर

मुंबई। ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट में एक अहम उपलब्धि हासिल हुई है। 'नायक' नाम की पहली टनल बोरिंग मशीन (TBM) के बाद, प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर 'मेघा इंजीनियरिंग' ने दूसरी विशाल मशीन 'अर्जुन' (TBM अर्जुन) को काम पर लगाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे की तरफ एक बटन दबाकर 'व्हाइट अर्जुन' का ऑपरेशन शुरू किया। 11.84 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 10.25 किलोमीटर की ट्विन टनल और 1.59 किलोमीटर की कनेक्टिंग सड़कें शामिल हैं। इससे ठाणे में घोड़बंदर रोड और बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच सीधा अंडरग्राउंड लिंक मिलेगा। पूरा होने पर, यात्रा का समय 60-90 मिनट से घटकर सिर्फ 15 मिनट रह जाएगा और उम्मीद है कि 2029 तक हर दिन लगभग 80,000 गाड़ियां इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगी।

तकनीकी जानकारीः

* भारत की सबसे बड़ी हार्ड-रॉक TBM: 13.34 मीटर व्यास, 86 मीटर लंबाई, 2,500 टन वजन।
* सिंगल-शील्ड, ओपन-टाइप TBM जिसे खास तौर पर MEIL के लिए जर्मन कंपनी हेरेनक्नेक्ट (Herrenknecht) ने डिजाइन किया है।
* अधिकतम गहराईः 23 मीटर।

'नायक' और 'अर्जुन' दोनों ही भारत में अब तक इस्तेमाल की गई सबसे बड़ी सिंगल-शील्ड हार्ड-रॉक TBM हैं। यह प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ट्रैफिक जाम को कम करेगा, हवा और शोर के प्रदूषण को घटाएगा और सस्टेनेबल शहरी विकास को काफी बढ़ावा देगा।

जौनपुर : कागज पर पाठशाला, धरातल पर मधुशाला

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। आम आदमी पार्टी के स्कूल खोजो अभियान में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सिकरारा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सादात बिंदुली को सरकारी यू-डायस रिकॉर्ड में संचालित दर्शाया गया है, जबकि धरातल पर विद्यालय बंद मिला। पूर्वांचल प्रांत प्रभारी डॉ. अनुराग मिश्र के नेतृत्व में एन.एन. तिवारी, विजय सिंह बागी एवं विद्याधर की टीम ने विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया। विद्यालय पर ताला लगा था, परिसर में भारी गंदगी और शराब की खाली बोतलें पड़ी मिलीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय लगभग एक वर्ष से बंद है। यह स्कूल खोजो अभियान के तहत सामने आया तीसरा मामला है। इससे पहले टीम ने सिकरारा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मीरगंज खास और बक्शा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय चपरामऊ की भी जमीनी स्थिति सामने रखी थी। डॉ. अनुराग मिश्र ने कहा कि योगी आदित्यनाथ, कागजों पर स्कूल चलाना बंद करिए और हमारे स्कूलों की चोरी करना बंद करिए। यू-डायस पर पाठशाला Operational है और जमीन पर ताला लगा है–यह कैसी शिक्षा व्यवस्था है? बच्चों के स्कूल बंद हैं और स्कूल परिसर शराब की बोतलों का अड्डा बन रहे हैं। उन्होंने कहा, आप स्कूलों को चाहे आसमान में छुपाकर रखें, पाताल में रखें या किसी गुफा-सुरंग में–हम उन्हें खोज निकालेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी, बहुत जल्द आपके गृह जनपद गोरखपुर में भी चोरी किए गए विद्यालयों को खोजकर जनता के सामने लाएंगे। डॉ. मिश्र ने कहा कि स्कूल खोजो अभियान जारी रहेगा। एक-एक विद्यालय की जमीनी हकीकत जनता के सामने रखी जाएगी और सरकारी रिकॉर्ड तथा धरातल के बीच अंतर के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। बच्चों के स्कूल वापस खोलिए, सुविधाएं बहाल कराइए और उन्हें शिक्षा दीजिए–कागजी आंकड़ों से बच्चों का भविष्य नहीं बनता।

राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के हाथों उद्घाटन

मुंबई। राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, ने गुरुवार को नरिमन पॉइंट पर RPG आर्ट फाउंडेशन की नई पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन 'ओवरशूट-लीनिंग इकोलॉजी' का उद्घाटन किया। मुंबई के इतिहास और भविष्य की झलक दिखाती ये इंस्टॉलेशन कलाकार अरुण कुमार एचजी ने बनाई है। राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभे के स्पीकर, उद्घाटन के मौके पर कहा, "RPG आर्ट फाउंडेशन द्वारा की गई यह सार्वजनिक कला स्थापना हमारे शहर के विकास को खूबसूरती से दर्शाती है। यह हाथी, प्राचीन घारापुरी की गुफाओं और उससे उत्पन्न आधुनिक वास्तुकला की ओर इशारा करता है, जो अतीत और भविष्य के संतुलन को दिखाता है। यह सच में पूरी तरह से मुंबई की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे शहर की स्थिरता के आदर्शों को बनाए रखने के लिए RPG ग्रुप का शानदार काम।" अरुण कुमार एच जी, कलाकार ने कहा, मुंबई के ऐसे महत्वपूर्ण स्थान के लिए कला बनाने का अवसर देने के लिए मैं आरपीजी आर्ट फाउंडेशन का बहुत आभारी हूं। ऐतिहासिक एलेफेंटा गुफा और वहाँ की भव्य मूर्तिकला ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। इस काम में मैंने मुंबई के दो समय को एक साथ लाने की कोशिश की है - शहर की आधुनिक आकांक्षाएं और उसके आधार पर खड़े गहरे ऐतिहासिक परिदृश्य। मैं खास तौर पर डॉ. भाऊ दाजी लाड म्यूज़ियम में मौजूद घारापुरी हाथी से प्रेरित हुआ हूँ, जो याद दिलाता है, शक्ति और द्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य की सतत उपस्थिति याद दिलाता है। यह कलाकृति आज के तेज़ी से बदलते शहर के साथ इन इतिहासों का संवाद करने की कोशिश है।

कार्य सम्राट विधायक मूरजी पटेल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया

मुंबई (उत्तरशक्ति)। कार्य सम्राट विधायक मूरजी पटेल का जन्मदिन गत सोमवार को सार्वजनिक बालवाड़ी, पवई-अंधेरी में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। जन्मदिन समारोह में क्षेत्र के नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने लोकप्रिय विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अशोक मूर्ति, आदित्य मूर्ति, सुखदेव गायकवाड, अविनाश मस्तूर सहित सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने विधायक मूरजी पटेल के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर जनसेवा के लिए शुभकामनाएं दीं।

समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि विधायक मूरजी पटेल ने अपने क्षेत्र के विकास और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। इसी वजह से उनके जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह रहा। महिला-पुरुषों और समर्थकों की बड़ी मौजूदगी के बीच जन्मदिन समारोह एक सामाजिक मिलन के रूप में भी नजर आया। उपस्थित लोगों ने विधायक को पुष्पगुच्छ देकर एवं शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के अंत में विधायक मूरजी पटेल ने उपस्थित सभी नागरिकों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास ही उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर का एरो ब्लैक एडिशन लॉन्च

मुंबई। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने आज अर्बन क्रूज़र हायराइडर एरो ब्लैक एडिशन के लॉन्च की घोषणा की। यह नयी लिमिटेड-एडिशन एसयूवी बोल्ड, यूथफुल और प्रीमियम डिजाइन एक्सप्रेशन के साथ लोकप्रिय लाइनअप में एक आकर्षक नया विकल्प जोड़ती है। स्टाइल-कॉन्शियस और डिजाइन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया एरो ब्लैक एडिशन, हायराइडर की रोड प्रेजेंस को ब्लैक्ड-आउट डिजाइन एलिमेंट्स और स्पोर्टी एक्सेंट्स के साथ और ऊँचा करता है, जिससे यह और भी डायनामिक, कमांडिंग और मॉडर्न स्टांस प्रदान करता है। अर्बन क्रूज़र हायराइडर एक्सक्लूसिव एरो ब्लैक एडिशन के सभी ग्रेड्स में ब्लैक एक्सटीरियर एन्हांसमेंट्स दिए गए हैं, जो इसके लुक को और आकर्षक बनाते हैं। इसमें दिया गया 'फ्रंट ग्रिल अपर गार्निश' एसयूवी के बोल्ड फ्रंट फेसिया को स्लीक और प्रीमियम लुक प्रदान करता है, जबकि 'फ्रंट स्पॉइलर' गाड़ी को अधिक शार्प, डायनामिक और स्पोर्टी स्टेंस देता है। इसके 'हेडलैम्प गार्निश' से फ्रंट-एंड डिजाइन को एक डिस्टिंक्टिव और सोफिस्टिकेटेड अपील मिलती है। पीछे के हिस्से की बात करें तो, 'टेलगेट गार्निश' रियर प्रोफाइल को बेहतर बनाते हुए एक सीमलेस प्रीमियम फिनिश तैयार करता है और 'रियर स्पॉइलर' एसयूवी को स्पोर्टी टच देने के साथ इसकी रोड प्रेजेंस को और ऊँचा करता है। इसके साथ ही, गाड़ी पर दिया गया 'एक्सक्लूसिव एरो ब्लैक लिमिटेड एडिशन बैज' एक खास स्टाइलिंग एलिमेंट के रूप में इस नई एसयूवी की एक्सक्लूसिविटी को हाइलाइट करता है। अर्बन क्रूज़र हायराइडर एरो ब्लैक एडिशन स्टाइलिंग पैकेज 31,999/- रुपयों में मिडनाइट ब्लैक और ग्रेड्स (नियो ड्राइव और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) पर उपलब्ध है और यह लिमिटेड पीरियड के लिए (स्टॉक रहने तक) ऑफर किया जाएगा। ग्राहक अपनी गाड़ी को और कस्टमाइज कर सकते हैं डीलर-लेवल वैल्यू-एडेड ऑल ब्लैक पैकेज के साथ, जो अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध होगा। 2022 में लॉन्च होने के बाद से अर्बन क्रूज़र हायराइडर भारतीय एसयूवी ग्राहकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है और 2 लाख बिक्री का माइलस्टोन पार कर चुका है। टोयोटा की वैश्विक एसयूवी विरासत पर आधारित अर्बन क्रूज़र हायराइडर बोल्ड स्टाइलिंग, उन्नत तकनीक और दैनिक व्यवहारिकता को जोड़ता है, जिससे यह ग्राहकों की पसंदीदा गाड़ी बन गई है। एरो ब्लैक एडिशन एसयूवी की प्रीमियम अपील को सोच-समझकर तैयार किए गए स्टाइलिंग तत्वों के जरिए और बढ़ाता है। यह एक मजबूत, स्पोर्टी सौंदर्य तैयार करता है जो सड़क पर अलग दिखाई देता है और इ-एसयूवी सेगमेंट में अर्बन क्रूज़र हायराइडर की विशिष्ट पहचान को और मजबूत बनाता है।

लायंस क्लब ऑफ पटना मगध ने किया तिरंगा यात्रा का आयोजन

पटना। लायंस क्लब ऑफ पटना मगध ने बच्चों में देश प्रेम की भावना के साथ एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के बच्चे शामिल हुए। बच्चों ने देश प्रेम से ओत-प्रोत होकर राष्ट्र प्रेम के गीत गाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली, जो टेंडर हर्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के सीनियर बिल्डिंग से शुरू हुई। हाथों में तिरंगा लिए बच्चों ने स्कूल की मोटेसरी बिल्डिंग तक यात्रा की उसके बाद बच्चे वापस मेन बिल्डिंग में लौट आए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके संघर्ष और देश के लिए दिए गए बलिदान पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ पटना मगध के अध्यक्ष लायन डॉ. रवि भार्गव, लायन डॉ. जुली भार्गव, रीजन जीईटी कोऑर्डिनेटर लायन राजीव भार्गव, कोषाध्यक्ष शिवानी भार्गव, लायन रेवा भार्गव एवं मैनेजर देव ज्योति सिन्हा उपस्थित रहे।

नारायणा हेल्थ और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच नॉलेज-शेयरिंग साझेदारी

मुंबई। नारायणा हृदयालय लिमिटेड (नारायणा हेल्थ) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने नॉलेज-शेयरिंग साझेदारी की है। इसके तहत नारायणा हेल्थ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करके एनडीबी और उसके सदस्य देशों को स्मार्ट अस्पतालों की क्षमता मजबूत करने में सहयोग करेगा। इसमें तकनीक आधारित, बेहतर और मरीज-केंद्रित अस्पताल सेवाओं को विकसित करने पर जोर रहेगा। एनडीबी और नारायणा हेल्थ के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर एनडीबी की प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ और नारायणा हेल्थ के फाउंडर एवं चेयरमैन डॉ. देवी शेट्टी ने जयपुर में हस्ताक्षर किए। इस दौरान भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव और एनडीबी में भारत की अल्टरनेट गवर्नर श्रीमती अनुराधा ठाकुर भी मौजूद रहीं। यह एमओयू पहले ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग के दौरान साइन किया गया। एनडीबी और नारायणा हेल्थ के बीच सहयोग के तहत डिजिटल हेल्थ, डेटा सिस्टम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नॉलेज शेयरिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। एनडीबी की प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ ने कहा, यह एमओयू एनडीबी और नारायणा हेल्थ के बीच एक संस्थागत साझेदारी है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हेल्थकेयर में उत्कृष्टता, इनोवेशन, दक्षता और किफायती इलाज एक साथ संभव हो, बल्कि हर्षें एक साथ होना ही चाहिए। आज एमओयू पर हस्ताक्षर होना सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की एनडीबी की प्राथमिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साझेदारी पर नारायणा हेल्थ के फाउंडर और चेयरमैन डॉ. देवी शेट्टी ने कहा, इस नॉलेज-शेयरिंग साझेदारी के जरिए हम एनडीबी और उसके सदस्य देशों के साथ मिलकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत और तकनीक आधारित हेल्थकेयर सिस्टम तैयार करने में सहयोग करने की उम्मीद करते हैं। मार्च 2026 में बेंगलुरु स्थित नारायणा हेल्थ सिटी के दौरे के दौरान डिल्मा रूसेफ ने मरीज-केंद्रित देखभाल और आधुनिक डिजिटल तकनीकों के जरिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संस्थान के प्रयासों को देखा था।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की समीक्षा बैठक में गूंजे पत्रकार एकता के स्वर

-अमित सिंह

हरदोई (उत्तरशक्ति)। कछौना (हरदोई)। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (ग्रापए) का राष्ट्रीय विस्तार लगातार तेज हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में संगठन देश के 12 प्रदेशों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है और चार अन्य प्रदेशों में संगठन को सशक्त स्वरूप देने के लिए संपर्क एवं सदस्यता अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में 62 जिलों में संगठन की इकाइयां कार्य कर रही हैं। 10 जिलों में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। यह विचार कछौना ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष अतुल कपूर ने व्यक्त किए। इस अवसर पर संडीला तहसील और भरावन ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में संडीला तहसील व भरावन ब्लॉक क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक पत्रकारों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार योगेश त्रिपाठी को संडीला तहसील का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया। वहीं सतेंद्र यादव शेरा को भरावन ब्लॉक अध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक एसबी सेंगर को सदस्यता अभियान प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। योगेश त्रिपाठी के संगठन महामंत्री बनाए जाने पर पत्रकार साथियों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और स्मृति चिह्न

भेंट कर सम्मानित किया।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतुल कपूर ने कहा कि संगठन अब केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारों की एकजुटता और उनके सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और तहसील स्तर के पत्रकार लोकतंत्र की जमीनी आवाज हैं और उन्हें एक मजबूत मंच उपलब्ध कराना संगठन की प्राथमिकता है। मंडल अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। पत्रकारों के सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह बबलू ने कहा कि पत्रकारों के सम्मान और हितों के लिए संगठन सदैव तत्पर रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंह ने पत्रकारों से निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता करने का आह्वान किया।

मंडल महामंत्री मुकेश सिंह आशा ने कहा कि खबर प्रकाशित करते समय दोनों पक्षों को सामने रखना पत्रकारिता की विश्वसनीयता के लिए बेहद आवश्यक है। लखनऊ मंडल के महासचिव जितेंद्र सिंह भाभी ने कहा के लखनऊ मंडल के रायबरेली, लखीमपुर और उन्नाव जनपद में सीकरी समीक्षा बैठकर आयोजित की जाएगी। तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह सोमवंशी ने कहा कि पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके सम्मान के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है। पत्रकार समाज की आवाज हैं और उनकी कलम की स्वतंत्रता एवं गरिमा बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। संगठन पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े हर सकारात्मक प्रयास में मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा। बैठक में संगठन की सदस्यता बढ़ाने, ग्रामीण पत्रकारों को एकजुट करने और तहसील से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा हुई। नवनियुक्त पदाधिकारियों को वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं देते हुए संगठन के उद्देश्यों और पत्रकार हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। इस अवसर पर मनोज जायसवाल संरक्षक, हरिश्याम बाजपेई, धनीराम श्रीवास्तव, अनुज कुमार मिश्रा, संजय, पुनीत पटेल, रमाकांत त्रिपाठी, अजय बाजपेई, करुणेन्द्र तिवारी, सूरज गुप्ता, सीपी मौर्या, अमन विश्वकर्मा, अरविंद सिंह, सुधीर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

होम क्रेडिट इंडिया का नया कैंपेन खुदपरनिर्भर रोजमर्रा की वित्तीय स्वतंत्रता को उजागर करता है

मुंबई। होम क्रेडिट इंडिया, एक अग्रणी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, ने अपने नए स्वतंत्रता दिवस ब्रांड कैंपेन खुदपरनिर्भर को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो खुद के वित्तीय फैसले लेने की आजादी का जश्न मनाता है। यह अभियान इस विश्वास पर आधारित है कि स्वतंत्रता केवल साल में एक बार मनाया जाने वाला सामूहिक माइलस्टोन नहीं है, बल्कि यह लाखों भारतीयों के लिए एक रोजमर्रा की व्यक्तिगत उपलब्धि भी है। यह अभियान वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के हर एक व्यक्तिगत क्षण को उस भारत के रूप में दर्शाता है जो एक समय में एक फैसला लेकर अधिक आत्मनिर्भर बन रहा है। यह कैंपेन सुलभ और सुविधाजनक वित्तीय साल्यूशन्स के साथ उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए होम क्रेडिट इंडिया की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, साथ ही ब्रांड के मूल दर्शन #जिंदगीहिट को भी जीवंत करता है। यह फिल्म विभिन्न लिंग, उम्र, स्थान और जीवन के पड़ावों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 प्रमुख घटनों को दर्शाती है। अपना पहला दोपहिया वाहन खरीदने और खुद कॉलेज की फीस भरने से लेकर व्यवसाय शुरू करने, घर का रिनोवेशन करने या कृषि में निवेश करने तक, यह कैंपेन उन कई तरीकों को दिखाता है जिनसे रोजमर्रा के जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता नजर आती है। फिल्म की शुरुआत कानपुर की एक 24 वर्षीय युवती से होती है, जो कैमरे के सामने सीधे अपनी पहली स्कूटर खरीदने की उपलब्धि के बारे में बात करती है। इसके बाद कैमरा पीछे हटता है और जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों और पीढ़ियों के अधिक लोगों को दिखाता है।